page 1 and 8 June 18_page 1 Mar 25 final ds.qxd 6/18/2026 1:36 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 रेलवे ऑफिसर क्लब जम्मू में महिला कल्याण संगठन द्वारा वृक्षारोपण

5 हमारे पास इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सबसे अच्छा मौका: हैरी

8 हिन्दी के बढ़ते कदम- जम्मू मंडल राजभाषा समिति की बैठक संपन्न

मौसम जम्मू — न्यूनतम 28 — अधिकतम 38

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-149 | जम्मू तवी, वीरवार 18 जून, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

जी-7 में बोले मोदी, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सभी मिलकर काम करें

प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को आश्वस्त किया कि भारत आने वाले समय में भी उनके साथ मिलकर साझा आर्थिक मजबूती के लिए अधिक स्थिर, विश्वसनीय तथा समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए कार्य करता रहेगा।

नयी दिल्ली 17 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 देशों से साझा वैश्विक समृद्धि की दिशा में काम करने का आह्वान करते हुए कहा है कि भारत विभाजन में नहीं, बल्कि एकीकरण, संरक्षणवाद नहीं, बल्कि भागीदारी और अनिश्चितता नहीं बल्कि साझा समृद्धि में विश्वास रखता है।प्रधानमंत्री ने बुधवार को फ्रांस के एवियन शहर में जी-7 देशों के 52 वें शिखर सम्मेलन में भागीदार देश के रूप में सभी के लिए संतुलित, साझा और टिकाऊ आर्थिक विकास विषय पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया। साझा समृद्धि पर विचार रखते हुए उन्होंने जी-7 देशों से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीप देशों के साथ व्यापार बढाने के लिए एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंटरनेशनल मोबिलाइज़ेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड (इम्पेक्ट) बनाने के साथ-साथ विकसित और विकासशील देशों के बीच ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भारत का साझा वैश्विक

समृद्धि में विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि यह कार्यों में भी दिखायी देता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस बैठक में उपस्थित अधिकांश देशों के साथ व्यापार समझौते किये हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है , भारत विभाजन में नहीं, बल्कि एकीकरण, संरक्षणवाद नहीं, बल्कि भागीदारी और अनिश्चितता नहीं बल्कि साझा समृद्धि में विश्वास रखता है।

प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों को आश्वस्त किया कि भारत आने वाले समय में भी उनके साथ मिलकर साझा आर्थिक मजबूती के लिए अधिक स्थिर, विश्वसनीय तथा समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए कार्य करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा , यह अछी बात है कि जी- 7 ने फ्रांस की अध्यक्षता में इस विषय को महत्व दिया है। आज सचाई यह है कि जब विकास की बात आती है, तो सवाल जीडीपी या व्यापार के आंकड़ों के बारे में नहीं होना चाहिए।असली सवाल यह है - विकास किसके लिए, किसके साथ और किस दिशा में? प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विकास को आकांक्षाओं से वास्तविकता में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा , जब भारत आगे बढ़ता है, तो वैश्विक आबादी का छठा हिस्सा आगे बढ़ता है। इसलिए भारत की विकास यात्रा पूरी मानवता के लिए समावेश, पैमाने और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की कहानी है। उन्होंने कहा , पिछले 12 वर्षों में भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूलमंत्र पर आगे बढ़ा है जो हमारे वैश्विक संबंधों का सिद्धांत है। जी 20 देशों की अध्यक्षता के दौरान भारत ने एक पृथ्वी , एक परिवार, एक भविष्य का संदेश पूरे विश्व को दिया जो हमारी सभ्यता की उस भावना का विस्तार था, जो विश्व को एक परिवार मानती है। श्री मोदी ने कहा कि इसी भावना से हमने भारत- पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे यानि आई-मेक, जैसी ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। यह एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला रणनीतिक गलियारा है, जो व्यापार को गति देगा, आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत बनाएगा, और साझेदार देशों में निवेश, रोज़गार और नवाचार के नए अवसर पैदा करेगा।

12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को सुरक्षा का मजबूत गढ़ बनाया : अमित शाह

नयी दिल्ली 17 जून। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने बुधवार को मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस अवधि में भारत को एक ऐसे 卐सुरक्षा के मजबूत गढ़卐 के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है, जो अपने नागरिकों की रक्षा करता है और खतरों का दृढ़ता से मुकाबला करता है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें पूरी दुनिया सराह रही है।

उन्होंने कहा, मोदी सरकार के 12 वर्षों में हमारे राष्ट्र का पुनर्निर्माण एक ऐसे सुरक्षा गढ़ के रूप में हुआ है, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अपने दुश्मनों को करारा जवाब देता

है।

अमित शाह ने कहा कि चाहे सीमा पार दुश्मनों को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब देना हो, या फिर अनुच्छेद 370 को हटाना, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाना अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 12 से अधिक शांति समझौतों के जरिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना हो, भारत ने हर क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।

उन्होंने कहा कि इन कदमों ने भारत को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है तथा दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

पिछले सप्ताह Narendra Modi भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने लगातार 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री Jawaharlal Nehru के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और सीमाओं की रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिनके परिणामस्वरूप देश पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और सशक्त बना है।

खबर संक्षेप

एनआईए ने यूएपीए के तहत बारामूला जिले में जमीन के दो भूखंड कुर्क किए

बारामुला, 17 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में जमीन के दो भूखंड कुर्क किए।

अधिकारियों ने कहा कि कनिसपोरा में 7.5 मरला (2,050 वर्ग फुट) और 6 मरला (1,632 वर्ग फुट) के भूखंड शाहीन अहमद लोन के हैं जो 2020 में एनआईए द्वारा दर्ज एक मामले में आरोपी हैं।

यह कुर्की यूएपीए की धारा 33 (1) के तहत जम्मू में एक नामित एनआईए अदालत द्वारा जारी आदेश के आधार पर की गई ।

यह कुर्की भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तानी राज्य एजेंसियों से जुड़ी गहरी साजिश की एनआईए की हाई-प्रोफाइल जांच का हिस्सा है। जांच अवैध हथियार नेटवर्क, आतंकी फंडिंग और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह के साथ हिजबुल आतंकवादियों को पकड़ने पर केंद्रित है।

नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने राज्य का दर्जा बहाली को लेकर एनसी के प्रस्तावित प्रदर्शन को बताया 'दिखावा'

श्रीनगर, 18 जून। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Sunil Sharma ने बुधवार को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन को महज दिखावा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि Jammu & Kashmir National Conference की सरकार अपनी शून्य शासन व्यवस्था से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने कहा, यह केवल एक दिखावा है। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने की घोषणा की है, ताकि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे की याद दिलाई जा सके। शर्मा ने कहा कि लोग बिजली की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई समीक्षा बैठक होते नहीं देखी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है और सरकार इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार चरम पर है और इसके बिना कोई काम करवाना मुश्किल हो गया है। इन छह मंत्रियों वाली सरकार ने केवल भ्रष्टाचार का माहौल बनाया है। जमीनी स्तर पर न तो शासन दिखाई देता है और न ही कोई प्रदर्शन। यह पूरी तरह से शून्य शासन और शून्य प्रदर्शन वाली सरकार है।

मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की

श्रीनगर, 17 जून। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना * तथा अन्य फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि उत्पादन विभाग), जम्मू-कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक, कृषि निदेशक कश्मीर एवं जम्मू, यूटीएलबीसी के संयोजक तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किसान ऋण पोर्टल पर दर्ज सभी पात्र किसानों को योजना के दायरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने संबंधित विभागों, बैंकों और अन्य हितधारकों को आपसी समन्वय से कार्य कर पात्र किसानों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अटल डुल्लू ने कहा कि चलाया जा रहा खेत बचाओ अभियान' किसानों में जागरूकता

फैलाने और उन्हें फसल बीमा का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने का प्रभावी मंच बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसानों को बीमा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन के महत्व से अवगत कराने और उन्हें इस किसान हितैषी योजना से जोड़ने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बैंकों को भी अपने **किसान क्रेडिट कार्ड धारकों तक पहुंच बनाकर उन्हें पीएमएफबीवाई में शामिल करने के निर्देश दिए।

जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए मुख्य सचिव ने कृषि उत्पादन विभाग को प्रत्येक जिले के लिए **नोडल अधिकारी** नियुक्त करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी बैंकों, बीमा कंपनियों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाधाओं की पहचान एवं समाधान करेंगे तथा पात्र किसानों के निर्बाध पंजीकरण और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले फसल नुकसान से किसानों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सभी हितधारकों को मिलकर बीमा कवरेज बढ़ाने और किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कार्य करना चाहिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन विभाग डॉ. आशीष चंद्र वर्मा ने योजना के आरंभ से अब तक के प्रदर्शन, खरीफ 2025 के दावों की

किसानों के अधिकतम कवरेज और दावों के समयबद्ध निपटारे पर दिया जोर

स्थिति, रबी 2025-26 के दौरान कवरेज, ऋण लेने वाले किसानों के कवरेज तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा के लाभों के बारे में ग्रामीण स्तर पर व्यापक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि मीडिया के अलावा 'खेत बचाओ अभियान' तथा अन्य सरकारी जनसंपर्क कार्यक्रमों का उपयोग भी किसानों को योजना की जानकारी देने और उन्हें लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने में किया जाएगा। कृषि निदेशक, कश्मीर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पीएमएफबीवाई लागू होने के बाद से अब तक 12.89 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि 6.85 लाख से अधिक किसानों को दावा भुगतान का लाभ मिला है।

राजौरी के जंगलों में 'ऑपरेशन शेरूवाली' का 26वां दिन; सुरक्षा बलों ने आतंकवाद-विरोधी तलाशी अभियान किया तेज़

राजौरी, 17 जून। राजौरी ज़िले के मंजाकोट सेक्टर में गंभीर मुग़लान इलाके के घने डोरीमल जंगलों में ऑपरेशन शेरूवाली बुधवार को अपने 26वें दिन में प्रवेश कर गया। यह हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में चल रहे सबसे लंबे समय तक चलने वाले आतंकवाद-विरोधी अभियानों में से एक बन गया है। सुरक्षा बलों ने मुश्किल पहाड़ी और जंगली इलाकों में तलाशी और घेराबंदी के अभियान तेज़ कर दिए हैं। यह ऑपरेशन डोरीमल की ऊबड़-खाबड़ और घने जंगलों वाली पहाड़ियों में चलाया जा रहा है जहाँ खड़ी ढलान पथरीले पहाड़ और घनी वनस्पति ज़मीन पर मौजूद सैनिकों के लिए बड़ी चुनौतियाँ पैदा कर रहे हैं। मुश्किल हालात के बावजूद सुरक्षाकर्मी पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए पूरे जंगल इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन के तहत निगरानी और इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने के उपाय भी जारी हैं।

ऑपरेशन शेरूवाली एक बड़े पैमाने का मल्टी-

एजेंसी आतंकवाद-विरोधी मिशन है जिसे मई के आखिर में शुरू किया गया था। इसका मकसद हथियारों से लैस उन घुसपैठियों का पता लगाना और उन्हें खत्म करना है जिनके डोरीमल-गंभीर मुग़लान सेक्टर के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में छिपे होने की आशंका है। इतने लंबे समय तक चलने वाला यह ऑपरेशन राजौरी के सीमावर्ती ज़िले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

'पानी बचाओ' और 'खेत बचाओ' विषय पर मेगा कार्यक्रम आयोजित

सांबा, जून। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत कृषि विकास की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), सांबा ने जिला सांबा के गांव सुपवाल में 卐पानी बचाओ और खेत बचाओ卐 विषय पर एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम प्रोफेसर (डॉ.) संजय खजूरिया, मुख्य वैज्ञानिक (कृषि वानिकी) एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र सांबा के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और देखरेख में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला किसानों, किसानों तथा ग्रामीण हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण के महत्व, जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, जलवायु अनुकूल कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली उन्नत तकनीकों को अपनाने के प्रति जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. सौरव गुप्ता, वरिष्ठ कीट वैज्ञानिक, केवीके सांबा ने किया। उन्होंने जल संकट और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दीर्घकालिक कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल प्रबंधन की प्रभावी तकनीकें, वर्षा जल संचयन, एकीकृत कृषि प्रणाली तथा संरक्षण कृषि को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महिला किसानों की सक्रिय भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे कृषि और घरेलू प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती हैं।

जम्मू-कश्मीर में 25 जून तक बारिश और आंधी-तूफान की संभावना

श्रीनगर, 17 जून। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक आम तौर पर बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान जताया है। साथ ही लोगों को ज़रूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा कि 17 जून को मौसम आंशिक रूप से या आम तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है। कई जगहों पर खासकर दोपहर के समय हल्की बारिश थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश, गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 18 जून से 22 जून तक आम तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है। पूर्वानुमान के अनुसार 23 जून से 25 जून तक मौसम आंशिक रूप से या आम तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश, थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है। इस बीच मौसम विभाग ने बागवानों के लिए एडवाइज़री जारी की है जिसमें उन्हें सुबह-सुबह या सुबह के समय स्प्रे का काम करने को कहा गया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान कमज़ोर ढांचों, बिजली के खंभों, ऊपर से गुज़रने वाले तारों और पुराने पेड़ों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। विभाग ने आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं के दौरान बोटिंग और शिकारा की सवारी रोकने की सलाह भी दी है।

जम्मू पुलिस ने पंजाब में नारको-टेररिज्म के तीन सरगनाओं को गिरफ़्तार किया, हथियार व ड्रग्स बरामद

जम्मू, 17 जून। संगठित अपराध और नारको-टेररिज्म सिंडिकेट के ख़िलाफ़ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू पुलिस ने अमृतसर में तीन लोगों - सूरजदीप सिंह उर्फ सूरज (निवासी जंडियाला), हरप्रीत सिंह उर्फ राजू और जसप्रीत - को गिरफ़्तार किया है। इन पर मीरान साहिब, बिश्नाह, नगरोटा और गंगयाल पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज हैं। ये तीनों जम्मू ज़िले में लगभग 80 प्रतिशत नशीले पदार्थों की सप्लाई के लिए ज़िम्मेदार थे। यह गिरफ़्तारी एक हाई-लेवल और बारीकी से चलाए गए ऑपरेशन के बाद हुई है। पुलिस अधिकारियों ने यहां एक प्रेस वार्ता कर बताया कि ये आरोपी जम्मू कश्मीर में सक्रिय लाऊ गुज्जरऔर उसके नेटवर्क के बैकवर्ड लिंक्स(निचले स्तर के सहयोगी) थे जिन पर पहले से ही कई एफआईआर दर्ज थीं। लाऊ गुज्जर के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों - लतीफ़, बच्चू, मजीदा और मुश्ताक - की गिरफ़्तारी और पूछताछ के दौरान सूरज और राजू के नाम सामने आए थे। ये तीनों आरोपी जम्मू में दर्ज नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में बैकवर्ड लिंक्सका हिस्सा रहे हैं। ये तीनों आरोपी जम्मू और उसके आस-पास के ज़िलों सांबा और कठुआ में लगभग 20 फॉरवर्ड लिंक्स(आगे सप्लाई लेने वालों) को नशीले पदार्थों की सप्लाई करते थे। इस रणनीतिक छापेमारी में हथियार, कमर्शियल-ग्रेड के नशीले पदार्थ, लॉजिस्टिक्स से जुड़े उपकरण और गैर-कानूनी कामों में इस्तेमाल होने वाली महंगी लग्ज़री गाड़ियाँ ज़ब्त की गईं। तलाशी के दौरान, ईइसयू जम्मू टीम, एसएचओ मीरान साहिब और बिश्नाह, पंजाब पुलिस के पीएसआई की टीमों ने इनके कब्ज़े से एक एके-47 राइफ़ल और चालीस 40 ज़दि कारतूस एक स्टार पिस्तौल और उनतीस 29 ज़दि पिस्तौल कारतूस, चार 04 ज़दि 12 बोर कारतूस। लगभग 1.020 किलोग्राम नशीले पदार्थ, एक इलेक्ट्रॉनिक वज़न करने वाली मशीन, पैकिंग पैकेट/पाउच और पैकिंग टेप का एक रोल, लगभग 11,00,000 रुपये नकद, तीन मोबाइल फ़ोन, एक महिंद्रा थार, अमेज़ और स्विफ़्ट कार बरामद की।

पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश मामले में बारामूला में हिजबुल और लश्कर के मददगार की दो संपत्तियां एनआईए ने कीं कुर्क

नई दिल्ली, 17 जून । राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जम्मू-कश्मीर में अपने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने बारामूला में पाकिस्तान समर्थित आतंकी साजिश मामले के एक मुख्य आरोपित की दो संपत्तियों को कुर्क (अटैच) कर दिया है। यह मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़ा हुआ है।

जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपित शाहीन अहमद लोन नियंत्रण रेखा (एलओसी) के रास्ते पाकिस्तान से हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों की तस्करी में शामिल था। इन हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति बाद में कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हिजबुल मुजाहिद्दीन और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को की

जाती थी।

एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि लोन आतंकवादियों को फंड प्राप्त करने और उसे ट्रांसफर करने की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल था। आरोपी के खिलाफ जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत में मामला चल रहा है। एनआईए ने लोन को

एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि लोन आतंकवादियों को फंड प्राप्त करने और उसे ट्रांसफर करने की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल था

सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और मार्च 2021 में उसके खिलाफ यूए(पी) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

जम्मू की विशेष एनआईए अदालत के आदेशों के बाद यूए(पी) एक्ट की धारा 33 (1) के तहत यह कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई दोनों संपत्तियां जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के कनीसपोरा गांव में स्थित हैं। इनमें 7.5 मरला भूमि पर बना एक आवासीय मकान और 6 मरला भूमि का एक टुकड़ा शामिल है, जिस पर शेड का निर्माण किया गया था।

सोना सूख गया

चीन में हुनसेन नाम का राजा शासन करता था। वह बहुत कंजूस था। दान-पुण्य तो दूर, जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए भी धन नहीं निकालता था। उसके पास सोने-चांदी का अपार भंडार था, लेकिन वह किसी की मदद नहीं करता था। राजा के महल से कुछ दूरी पर सिनचिन नामक एक वृद्ध की छोटी-सी झोंपड़ी थी। सिनचिन उस समय चीन का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। राजा की आदतों से वह भी परेशान था। अतः उसने राजा को सबक सिखाने की ठान ली।

एक दिन वह अपने मित्रों से सोने के नन्हे-नन्हे चार टुकड़े उधार लाया। उसने सोने के उन टुकड़ों को पीली चमकती हुई एक बड़ी छलनी में रखा और पास बहती नदी के किनारे जा बैठा। इस नदी पर राजा रोज स्नान करने आता था। सिनचिन ने दूर से ही राजा को आते हुए देखा। वह ऐसा अभिनय करने लगा, मानो छलनी में कुछ छान रहा हो। राजा ने उसके पास आकर पूछा, ल्लसिनचिन, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें सुबह-सुबह रेत छानने की क्या आवश्यकता पड़ गई?
सिनचिन ने कहा, महाराज, मैं तो इस रेत में छिपा सोना ढूंढ़ रहा हूं.ल्क
राजा कुछ कहता, इससे पहले ही सिनचिन ने छलनी भर रेत निकाली और छान दी। छलनी के ऊपर सोने के चार छोटे-छोटे टुकड़े चमक रहे थे।
राजा ने आश्चर्य से पूछा, ल्लरेत में सोना! यह कैसे किया?
सिनचिन ने समझाते हुए जवाब दिया, ल्लहुजूर, आज से महीना भर पहले मैंने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा इस जगह पर बोया था। देखिए हुजूर, पूरे चार टुकड़े निकले हैं। यदि मैं कुछ और सब्र करता, तो यहां बहुत से टुकड़े मिलते।
राजा ने चौंकते हुए कहा, ल्लक्या बकवास करते हो? भला क्या सोने की भी खेती की जा सकती है?
सिनचिन ने कहा, क्यों नहीं हुजूर? आप खुद ही देख लीजिए। मैं तो गरीब आदमी हूं। पिछले दस वर्षों से इसी प्रकार सोना बोता हूं और काट लेता हूं। इसी सोने से मेरा पेट पलता है।
राजा ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो सोने का ढेर है। मुझे पता होता, तो मैं सारा सोना बो देता। आज तक तो मेरा महल सोने से भर गया होता।
इस पर सिनचिन ने कहा, हुजूर, अब भी देर नहीं हुई है। आप अब भी बो लीजिए। छह महीने बाद देखिएगा, तो फसल लहलहाती नजर आएगी।
राजा ने सिनचिन के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, देखो सिनचिन, तुम तो एक अनुभवी आदमी हो। मेरी ओर से तुम सोने की खेती करो। इसके लिए तुम्हें जितना सोना चाहिए, तुम ले सकते हो। आज ही मेरे साथ महल में चलो। इस काम के लिए तो तुम मेरे सेवकों को भी साथ ले सकते हो।
सिनचिन तो मानो इस मौके की प्रतीक्षा में था। वह तुरंत राजी हो गया। वह महल में गया और सोने के ढेरों टुकड़े ले आया। राजा ने अपने दस सेवक भी सिनचिन को मदद के लिए दे दिए।
देखते ही देखते, नदी के किनारे खुदाई का काम शुरू हो गया। सिनचिन के कहे अनुसार, सेवकों ने वहां पर सोना बीज की तरह बो दिया। ऊपर रेत डाल दी। सिनचिन ने राजा को आश्वासन दिया कि छह महीने बाद बोए हुए सोने का तीन गुना सोना मिल जाएगा।
इस बीच सिनचिन रोज रात को नदी किनारे जाने लगा। वहां पर वह रोज थोड़ा सा हिस्सा खोदता और वहां दबा सोना अपने झोले में रख लाता। अगले दिन सुबह ही वह सारा सोना गरीबों में बांट देता था। धीरे-धीरे जनता की गरीबी मिटने लगी।
इधर राजा इंतजार करता रहा कि कब छह महीने पूरे हों और उसे बोए हुए सोने का तीन गुना सोना मिले। धीरे-धीरे छह महीने भी पूरे हो गए। राजा ने सिनचिन को दरबार में बुलाया। उसे आदेश दिया कि वह सारा सोना खोद लाए। सिनचिन ने इस काम के लिए कुछ सेवकों की मांग की। राजा ने इस बार बीस सेवक उसके साथ कर दिए। सेवकों ने उस स्थान पर काफी गहराई तक खुदाई की, रेत को छाना। लेकिन सभी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उसमें सिवाय दो-चार सोने के टुकड़ों के कुछ नहीं था। सिनचिन भागा-भागा राजा के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, हुजूर, आपकी किस्मत खराब थी। जमीन में सोने के दो-चार सूखे हुए टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं निकला है।
राजा ने आश्चर्य से पूछा, ल्लसूखे हुए टुकड़े! तुम्हारा मतलब क्या है? सिनचिन ने जवाब दिया, हां हुजूर, इस बार सारा सोना सूख गया है। आप तो जानते ही हैं, इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सारी फसल सूख गई। आपका बहुत नुकसान हो गया इस बार।
हुनसेन ने डांटते हुए पूछा, भला सोना सूख कैसे सकता है? यह तो ठोस चीज है।
सिनचिन ने मुसकराते हुए कहा, हुजूर, आपने इतनी बातों पर विश्वास कर लिया कि सोना बोया जा सकता है, सोने की फसल लहलहा सकती है, सोना काटा जा सकता है। फिर भला इतनी सी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते कि सोना सूख गया?
राजा निरुत्तर हो गया। मंत्रियों से सलाह ली, तो उन्होंने कहा, सिनचिन ठीक कहता है। वाकई यदि सोना बोया जा सकता है, तो सूख भी सकता है। अब तो राजा से कुछ कहते नहीं बना। वह सिर पकड़कर बैठ गया। सिनचिन ने कंजूस राजा को अच्छा सबक सिखा दिया था।

अंतरराष्ट्रीय शोध टीम ने खोजी कछुए की नई प्रजाति

एक अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर जर्मनी के सेनकेनबर्ग के वैज्ञानिक यूवे फ्रिट्ज ने आनुवांशिक विश्लेषण के आधार पर कछुए की एक नई प्रजाति के बारे में बताया है। अब तक माना जाता था कि 'जीनस चेलुस' कछुए की केवल एक ही प्रजाति है। अध्ययन में कहा गया है कि उन जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिनको अक्सर अवैध पशु व्यापार में बेच दिया जाता है। इस अध्ययन को साइंटिफिक पत्रिका मॉलिक्युलर फाइटोलेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित किया गया है।

इस प्रजाति का नाम माता-माता बताया गया है, जो पानी के नीचे कीचड़ में छिपे रहते है, इनकी लंबाई 53 सेंटीमीटर तक होती है। ये शैवाल से ढकी चट्टानों की तरह दिखते हैं। लेकिन जब कोई शिकार करने लायक जानवर सामने आता है, तो कछुआ उसे अचानक अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे चूसकर पूरा निगल जाता है। ड्रेसडेन में सेनकेनबर्ग प्राकृतिक इतिहास संग्रह के प्रोफेसर डॉ.यूवे फ्रिट्ज बताते हैं यद्यपि ये कछुए अपने विचित्र रूप और असामान्य खाने के व्यवहार के कारण व्यापक रूप से जाने जाते हैं, लेकिन उनकी विविधता और आनुवांशिकी के बारे में बहुत कम जानकारी है। फ्रिट्ज कहते हैं अब हमने यह मान लिया कि इस कवचवाले सरीसृप की केवल एक प्रजाति है जो पूरे दक्षिण अमेरिका में व्यापक रूप से फैली हुई है।
लेकिन ऐसी प्रजातियां, जिन्हें लुप्तप्राय नहीं माना जाता है, वे आश्चर्यजनक हो सकती हैं। आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर, उन्हें अक्सर दो या अधिक स्वतंत्र प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। कई अध्ययनों से पता लगा है कि माता-माता कछुए अमेजन बेसिन की तुलना में ओरिनोको नदी में अलग दिखते हैं। ड्रेसडेन के वैज्ञानिक कहते हैं इस अवलोकन के आधार पर, हमने इन जानवरों के जेनेटिक बनावट पर बारीकी से नजर रखने का फैसला किया है।
75 डीएनए नमूनों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने बताया कि पिछली मान्यताओं के विपरीत, माता-माता कछुओं की आनुवंशिक और दिखने में भी भिन्न-भिन्न दो प्रजातियां हैं। नई प्रजातियां चेलुस ओरिनोकेन्सिस ओरिनोको और रियो नीग्रो बेसिन में निवास करती हैं, जबकि चेलुस फिम्ब्रिआटा के रूप में जानी जाने वाली प्रजाति विशेष रूप से अमेजॅन बेसिन तक सीमित है।
अध्ययन के अनुसार, लगभग 1 करोड़ 30 लाख साल पहले दोनों प्रजातियां मियोसीन के दौरान विभाजित हो गईं थी। इस अवधि के दौरान, पूर्व अमेजॅन-ओरिनोको बेसिन में जानी पहचानी दो नदी घाटियां अलग-अलग हो गई थी। कई जलीय जीवों की प्रजातियां इस तरह स्थान के आधर पर अलग हो गईं और इन्होंने आनुवंशिक रूप से फैलना शुरू कर दिया।
नई प्रजातियों के विवरण में भी माता माता के संरक्षण की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। आज तक, इस प्रजाति के व्यापक रूप से फैलने के कारण इन्हें लुप्तप्राय नहीं माना गया था। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि हमारे परिणाम बताते हैं कि, दो प्रजातियों में विभाजित होने के कारण, प्रत्येक प्रजाति की जनसंख्या आकार पहले की तुलना में छोटी हुई है।
इसके अलावा, हर साल इन विचित्र दिखने वाले हजारों जानवरों का अवैध व्यापार होने से इनका जीवन समाप्त हो रहा हैं।
हालांकि इन जानवरों के अवैध व्यापार का पता लगने पर अधिकारियों द्वारा इन्हें जब्त भी किया जाता है। बोगोटा के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलम्बिया के प्रोफेसर और प्रमुख अध्ययनकर्ता मारियो वर्गास-रामिरेज कहते है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, हमें इन आकर्षक जानवरों की रक्षा करनी चाहिए।

दुनिया की रहस्यमयी फुन्दूजी झील

दुनिया में लाखों की संख्या में झीलें हैं, कुछ झीलें ऐसा ही जिनका रहस्य आज तक इंसान नहीं जानता.कुछ झीलों काफी डारवनी भी है.आज हम आपको एक ऐसी ही झील के बारे में बताने जा रहे हैं.कहा जाता है कि इस झील का पानी जो भी पी ले वो जिंदा नहीं बचता है और जल्द ही उसकी मौत हो जाती है.यह रहस्यमयी झील दक्षिण अफ्रीका के लिंपोपो प्रांत में है. इसे फुन्दूजी झील के नाम से जाना जाता है.स्थानीय लोगों के अनुसार, किंवदंती है कि इस जगह से प्राचीन काल में एक कोढ़ी व्यक्ति जो कारी लंबा सफर करके यहां आया था, उसे लोगों द्वारा भोजन और आश्रय नहीं दिया गया. कहा जाता है कि इसके बाद उस व्यक्ति ने लोगों को श्राप दिया और झील में प्रवेश किया और फिर गायब हो गया.
कहा जाता है कि झील के अंदर से आज भी डूबे हुए लोगों के रोने, ड्रम बजने की आवाजें आती रहती हैं. स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पहाड़ों पर मौजूद इस झील की रक्षा एक विशालकाय अजगर करता है.इस अजगर को प्रसन्न करने के लिए हर साल वेन्दा आदिवासी एक नृत्य उत्सव का आयोजन करतें हैं, जिसमें कुवारी लड़कियां नाचती हैं.कहा जाता है कि झील प्राचीन काल में भूस्खलन के कारण बनी थी जिसने मुटाली नदी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया था, और अब यह एक रहस्य है कि नदी का पानी बहुत साफ है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो भी इसके पानी को पीता है उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है.
जानकारी के अनुसार, झील के पानी के रहस्य को जानने की कई कोशिशें हुईं, हालांकि जांचकर्ता हर बार विफल रहे. कहा गया कि 1946 में एंडी लेविन नाम के एक व्यक्ति को झील के पानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए यहां आया था.उसने इस झील से थोड़ा पानी लिया और झील के आस-पास के कुछ पौधे लिए और चल दिया. लेकिन वो थोड़ी देर ही चला था कि वो रास्ता भटक गया.एंडी लेविन तब तक रास्ता भटकते रहे जब तक उन्होंने पानी और पौधे नहीं फेंक दिए थे. हालांकि, इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी.
आज तक किसी को इस बात का पता नहीं चला है कि आखिर इस झील में ऐसा क्या है कि इसका पानी पीने के बाद व्यक्ति कि मौत हो जाती है.कुछ लोगों का मानना है कि इस झील के पानी में कोई खतरनाक जहरीली गैस मिली हो सकती है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है.

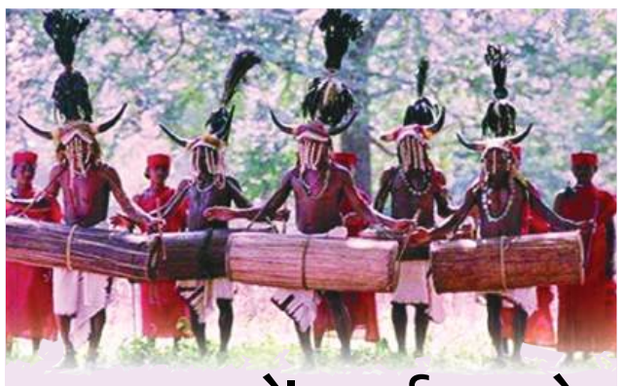

बस्तर में पाई जाने वाली जनजातियां

आधुनिक भारत में आज भी कई ऐसे स्थान है जहां पर बरसों से चली आ रही जनजातियां निवास करती हैयु तो भारतीय इतिहास में आदिवासी जनजाति संस्कृति का बहुत महत्व है.लेकिन समय के साथ बहुत सी जनजातियों ने स्वयं में बदलाव किये है.जैसे हलबा व भतरा जनजाति इत्यादि. अगर संपूर्ण विश्व की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनजातियां भारत में पाई जाती है जैसे कोल, भील, पहाड़िया, कमार, थारू जनजाति इत्यादि. लेकिन आज हम आपको बस्तर में पाई जाने वाली प्राचीन समय से लेकर अब तक चली आ रही जनजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं.ये जनजातियां बस्तर व बस्तर के आस पास के इलाको में निवास करती है.तो जानते हैं इन जनजातियों के बारे में

जनजाति का अर्थ

जनजाति को समझने के लिए पहले हमें प्रकृति व जंगलों में रहने वाले मनुष्य के समुदाय को बारीकी से समझना चाहिए.जनजाति वह होती है जो सभी लोगों से दूर पर्वतों,जंगलों, वनो इत्यादि में निवास करती हैं. जिन की भाषा अलग होती है जो भूत-प्रेत, दैवी शक्तियों में बेहद विश्वास रखते हैं. जिन का व्यवसाय जंगली शिकार व जंगली पेड़ पोधो पर निर्भर रहता है. जंगलो में पाई जाने वाली लगभग 90 % जनजातीय असभ्य व हिंसक होती हैजिस प्रकार जंगली जानवर अपने इलाके की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकता है ठीक इसी प्रकार ये जनजातीया अपने इलाके की रक्षा करती है. अमूमन सभी जनजाती माँसाहारी होती है.

बस्तर में पाई जाने वाली जनजातियों से पहले आपको बस्तर इलाके के बारे में समझना होगा.बस्तर एक जिला है जो चार संस्कृतियों से घिरा हुआ है इसके चारों तरफ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाएं लगती है.इस जिले के जंगलो में हजारों सालों से विभिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं जिनमे से प्रमुख जनजातियों का विवरण इस प्रकार है :

माडिया जनजाति

माडिया जनजाति बस्तर के जंगलों में पाई जाने वाली जनजाति है.यह जनजाति बस्तर के पहाड़ी इलाकों व जंगलों में निवास करती है.माडिया जनजाति को दो भागों में बांटा गया है 1.अबुझ माड़िया 2. दण्डामी माड़िया (बाईसन होर्न माड़िया) अबूझ मडिया पहाड़ों के घने जंगलों में निवास करती है व दण्डामी माड़िया समतल इलाके के जंगलों में निवास करती हैय़े लोग माड़िया भाषा बोलते है.इन दोनों जनजातियों की संस्कृति आपस में मिलती जुलती है और यह दोनों ही जनजातियां बाहरी लोगों का अपने इलाके में आना पसंद नहीं करती.जब भी कोई व्यक्ति इनके इलाके में प्रवेश करता है तो यह असहज महसूस करते हैं व बाहरी व्यक्ति पर तीर कमान से हमला कर देते हैं. हमले के बाद इस जनजाति के लोग कर्कश ध्वनि के द्वारा अपनी ताकत का एहसास कराते हैं.माडिया जनजाति के पुरुषों का स्वभाव नटखट व नाच गाने वाला होता है.यह लोग शराब के शौकीन होते हैं.इस जनजाति लोग अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अपने देवताओं के सम्मान में लकड़ियों के द्वारा आग जला कर उसके चारों ओर नृत्य करते हैं.माडिया जनजाति सर्वाहारी जनजातियों की श्रेणी में आती है.इस जनजाति के लोग बहुत बहादुर होते है ट इस जनजाति के पुरुष शिकार के लिए बाघ, भालू, तेंदवे से भी लोहा लेने से नहीं कतराते.यु तो माडिया जनजाति बाघ का बेहद सम्मान करती है परंतु जब बाघ इन पर हमला करता है तो आत्म रक्षा में बाघ को भी मार सकते है.माड़िया लोगो में घोटुल परंपरा का पालन होता है व यह लोग काकसार नाम के कुल देवता की अराधना करते हैं.

हलबा जनजाति

हलबा जनजाति छत्तीसगढ़ (बस्तर) में पाई जाने वाली एक विशाल जनजाति है इस जनजाति के लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में निवास करते हैं. प्राचीन समय में यह जनजाति भी जंगलों में रहती थी परंतु आज के समय में इस जनजाति के लोग गांवो की तरफ भी पलायन कर रहे हैं.हलबा जनजाति 17 वीं शताब्दी में बस्तर राज्य के प्रमुख और सबसे प्रभावशाली जनजातीय समूहों में से एक थीं व उस समय हलबा जनजाति बस्तर राज्य की राजनीति और सेना में सक्रिय थीं.देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवास के बाद हलबा जनजाति ने अपनी आजीविका के लिए अलग-अलग व्यवसाय को अपना लिया . जैसे कृषि, बुनाई, मजदूरी इत्यादि हल्बा जनजाति की भाषा हल्बी है, जो मराठी और ओडिया का संयोजन से बनी है व ये लोग देवी माँ दंतेश्वरी की पूजा करते है.

भतरा जनजाति

भतरा जनजाति प्राचीन काल में सम्पूर्ण बस्तर जिले में फैली हुई थी इस जनजाति के लोग कला और नाटक प्रेमी होते थे.इन्हें पेंटिंग करना व नाच गाना पसंद था.परंतु समय के साथ इस जनजाति के लोगो ने खुद में बदलाव किया और यह भी समय की दौड़ के साथ चलना सिख गए.आज भतरा जनजाति के लोगों ने आधुनिक बनना शुरू कर दिया है.इस जनजाति के लोग आज कल शहरों में रोजगार की लिए निवास करते हैं.प्राचीन समय में इस जनजाति के लोगो का प्रिय भोजन केकड़ा व पक्षियों का मॉस था.

मुरिया जनजाति

मुरिया जनजाति को बस्तर की मूल जनजाति कहा जाता है अर्थात इस जनजाति के लोग हमेशा से इस इलाके में रहे हैं इस जनजाति के लोगों को श्रृंगार करना व कलात्मक वस्तुएं बनाना पसंद है.मुरिया जनजाति में माओपाटा के रूप में एक आदिम शिकार नृत्य किया जाता है जिसमे इस जनजाति के सभी पुरुष बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते है.नृत्य के समय युवा पुरुष नर्तक अपनी कमर में पीतल अथवा लोहे की घंटियां बांधे रहते है साथ में छतरी और सिर पर आकर्षक सजावट कर नृत्य करते है.

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

जेडीए ने रेलवे स्टेशन के पास कब्जाई ज़मीन वापस ली, 30 से ज़्यादा अवैध निर्माण गिराए गए

जम्मू, 17 जून(हि.स.)। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेडीए) ने बुधवार को जम्मू रेलवे स्टेशन के पास एक तोड़-फोड़ अभियान चलाया जिसमें 30 से ज़्यादा अवैध ढांचों को हटाया गया और 10 करोड़ रुपये की कीमत वाली कब्ज़े वाली ज़मीन वापस हासिल की गई।

अधिकारियों ने बताया कि सुबह-सुबह की गई इस कार्रवाई में शहर की अहम ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए बैठे अनधिकृत कमर्शियल यूनिट्स (जैसे ढाबे और दुकानें) को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि जेडीए की टीमों ने ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर मंगल मार्केट के सामने वैष्णवी धाम के पीछे और जम्मू रेलवे स्टेशन के पास आधी एकड़ अहम ज़मीन वापस हासिल की। उन्होंने आगे बताया कि इस ज़मीन पर कई सालों से अनधिकृत कब्ज़ा था और दो लोग वहाँ कई ढाबे और कमर्शियल प्रतिष्ठान अवैध रूप से चला रहे थे।

कब्ज़ा करने वालों ने पहले हाई कोर्ट में अपने कब्ज़े को रेगुलर करने की अपील की थी। कोर्ट के निर्देशों के बाद सक्षम अधिकारी ने मामले की जाँच की और पाया कि कब्ज़ा अनधिकृत और कानून के तहत गैर-कानूनी था। इसके बाद कब्ज़े हटाने और ज़मीन जेडीए को वापस सौंपने के आदेश जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान 30 से ज़्यादा अनधिकृत ढांचों को खाली कराया गया और तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इन कब्ज़ों की वजह से रेलवे स्टेशन इलाके में गाड़ियों की भारी आवाजाही और सड़क किनारे पार्किंग से लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी जिससे यात्रियो पैदल चलने वालों और रेलवे यात्रियों को अक्सर परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कब्ज़े वाले इलाके के आस-पास गैर-कानूनी गतिविधियों की ओर भी बार-बार ध्यान दिलाया था जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा पर असर पड़ रहा था साथ ही ढाबों पर खाना भी अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया जा रहा था।

जेडीए के वाइस चेयरमैन रूपेश कुमार ने कहा कि सार्वजनिक ज़मीन जनता की अमानत है और इसे अवैध कब्ज़े से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, नियोजित विकास और शहरी बुनियादी ढाँचे को प्रभावित करने वाले कब्ज़ों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के लिए अथॉरिटी की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।

रेलवे ऑफिसर क्लब जम्मू में महिला कल्याण संगठन द्वारा वृक्षारोपण

महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा राखी कुमार और उपाध्यक्षा श्लेषना मरन्टू ने पौधा लगाकर की शुरुआत

पर्यावरण संरक्षण के लिए क्लब परिसर में रोपे गए विभिन्न प्रजातियों के छायादार और फलदार पौधे

जम्मू, 17 जून। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज रेलवे ऑफिसर क्लब, जम्मू में महिला कल्याण संगठन (जम्मू मंडल) की ओर से एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती राखी कुमार और उपाध्यक्षा श्रीमती श्लेषना मरन्टू द्वारा संयुक्त रूप से पौधा लगाकर की गई। इस सराहनीय पहल में संगठन की अन्य महिला सदस्यों के साथ वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान क्लब परिसर में विभिन्न प्रजातियों के छायादार एवं फलदार पौधे रोपित किए गए और साथ ही उनकी देखभाल व सुरक्षा का संकल्प भी लिया गया।

पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। आज का यह छोटा सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरा-भरा जम्मू बनाने की दिशा में एक कदम है। हम सभी महिलाओं से अपील करते हैं कि वे अपने घर-आंगन में भी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं।

श्रीमती राखी कुमार, अध्यक्षा (महिला कल्याण संगठन)*

महिला सदस्यों के उत्साह की सराहना करते हुए संगठन की उपाध्यक्षा श्रीमती श्लेषना मरन्टू ने कहा, महिलाएं जब किसी संकल्प को ठान लेती हैं, तो उसे पूरा करके दिखाती हैं। पर्यावरण सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और हम इसमें अपना निरंतर योगदान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।*

महिला कल्याण संगठन ने भविष्य में भी पर्यावरण को सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए ऐसे जागरूकता और वृक्षारोपण कार्यक्रमों को जारी रखने का अपना संकल्प दोहराया।

छात्रों और स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक

जम्मू, 17 जून (हि.स.)। नेशनल इनक्रेडिबल लिटरेसी मिशन (एनआईएलएम) द्वारा गंगा नगर बंतलाब स्थित अपने परियोजना केंद्र में नशा मुक्ति एवं परामर्श जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों और क्षेत्र के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को नशे के दुष्प्रभावों, इसके व्यक्ति, परिवार और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों तथा समय पर परामर्श और पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि उचित मार्गदर्शन और उपचार के माध्यम से नशे की गिरफ्त में आए लोगों को स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन की मुख्यधारा में वापस लाया जा सकता है।

इस अवसर पर एनआईएलएम जम्मू की पर्यवेक्षक कविता बाली, एम.एससी. काउंसलिंग एवं फैमिली थेरेपी विशेषज्ञ राकेश्वर सिंह तथा इंटर्नशिप छात्रों द्वारा निःशुल्क परामर्श सत्र आयोजित किया गया। काउंसलिंग टीम ने प्रतिभागियों के साथ संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया और नशे की लत से उबरने तथा उससे जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनआईएलएम के अध्यक्ष ठाकुर के.डी. कुरहान ने कहा कि नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम समाज के लिए अत्यंत लाभकारी हैं और नशे से प्रभावित लोगों को सम्मानजनक एवं स्वस्थ जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं।

उन्होंने दोहराया कि नेशनल इनक्रेडिबल लिटरेसी मिशन उन सभी लोगों को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जो नशे की लत छोड़कर समाज की मुख्यधारा में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पुनः स्थापित होना चाहते हैं।

कार्यक्रम के अंत में समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों और परिवारों से नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की गई। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

भारी बारिश के बाद कीगाम कुपवाड़ा में अचानक आई बाढ़

कुपवाड़ा, 17 जून (हि.स.)। भारी बारिश के बाद कीगाम कुपवाड़ा में अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली है। इस दौरान जलभराव और रुकावट की रिपोर्ट से बाढ़ जैसे हालात बन गए जिससे घरों और खेती की जमीन को नुकसान हुआ।

अधिकारियों ने कहा कि जलभराव की वजह से अचानक पानी और मलबा कई घरों में घुस गया और खेती की जमीन डूब गई। इस घटना से लोगों में घबराहट फैल गई जो पानी का लेवल तेजी से बढ़ने पर सुरक्षित जगहों पर भाग गए।

अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की और कहा कि प्रभावित गांव में पानी भरने से फसलों और घरों को नुकसान हुआ है। घटना के बाद रेवेन्यू अधिकारी और लोकल अधिकारी नुकसान का अंदाजा लगाने और स्थिति पर नज़र रखने के लिए इलाके में पहुंचे।

लोगों ने प्रशासन से इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए तुरंत राहत और मुआवज़े की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को ज़रूरी मदद दी जाएगी।

बड़ी उपलब्धि: देश के प्रतिष्ठित 2 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्लब में उत्तर प्रदेश हुआ शामिल

***लखनऊ, 17 जून।** उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 2 गीगावाट स्थापित क्षमता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश देश के प्रतिष्ठित 2 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्लब में शामिल हो गया है, जहाँ अब तक केवल गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अग्रणी राज्यों की उपस्थिति थी।

यह उपलब्धि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर बढ़ती जनभागीदारी का परिणाम मानी जा रही है। योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अपने घरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित कर स्वच्छ एवं सस्ती ऊर्जा को अपनाया है। इस दौरान यूपी नेडा रविंदर सिंह ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में यह उपलब्धि केवल एक सांख्यिकीय मील का पत्थर नहीं है, बल्कि प्रदेश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। घरेलू रूफटॉप सोलर के विस्तार से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिलने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिल रही है।

प्रदेश की इस सफलता में यूपीनेडा के इम्पैनल्ड वेंडर्स, विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, बैंकिंग संस्थानों तथा लाखों उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न विभागों और संस्थाओं के समन्वित प्रयासों ने सौर ऊर्जा को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में योगदान दिया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में घरेलू सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्तमान प्रगति को देखते हुए प्रदेश अब देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में अपनी स्थिति और मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है। अधिकारियों का मानना है कि यदि वर्तमान गति बनी रही तो आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों को चुनौती देते हुए नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश की यह उपलब्धि राज्य के हरित ऊर्जा भविष्य और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राज्य डेटा की साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने पर आयोजित परामर्श कार्यशाला में भाग लिया

लेह, 17 जून। लद्दाख के उपराज्यपाल Vinai Kumar Saxena ने आज राज्य डेटाके लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में भाग लिया। यह कार्यशाला भारत सरकार द्वारा सरकारी डेटा और डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एक मजबूत एवं लचीला ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई देशव्यापी परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है।

यह कार्यशाला माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने National Conference of Chief Secretaries* के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के नेतृत्व में विषय आधारित सम्मेलनों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच नियमित तथा संरचित संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया था।

यह कार्यशाला चार चरणों वाली परामर्श प्रक्रिया के दूसरे चरण का प्रतिनिधित्व करती है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान प्रणालियों और सरकारी कार्यप्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के कारण लद्दाख का डिजिटल विस्तार तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन से सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शिता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साइबर खतरों का जोखिम भी बढ़ा है।

उन्होंने बताया कि रैनसमवेयर हमले, डेटा चोरी, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन से जुड़े साइबर हमले तथा महत्वपूर्ण प्रणालियों तक अनधिकृत पहुंच जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र आवश्यक है।

भद्रवाह में हड़ताली सफाई कर्मियों को एनजीओ का समर्थन, बकाया वेतन व नियमितीकरण को लेकर प्रशासन पर साधा निशाना

आमिर इकबाल खान

भद्रवाह, 17 जून। सफाई कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को बुधवार को उस समय और बल मिला, जब प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन ऑल इंडिया पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी ने उनके समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। संगठन ने पिछले एक माह से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांगों की अनदेखी करने पर प्रशासनिक तंत्र की कड़ी आलोचना की। सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष जफ्फर हुसैन वानी के नेतृत्व में वरिष्ठ पदाधिकारी हिसाम-उद-दीन, उमर फारूक टाक और मोहम्मद सलीम भट सहित संगठन के सदस्य पुराना बस अड्डा स्थित भद्रवाह नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे और उनके आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की। इस दौरान जफ्फर हुसैन वानी ने कहा कि मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार तथा

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन की उदासीनता के कारण सफाई कर्मियों की जायज मांगें लंबे समय से अधर में लटकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अनेक धरना-प्रदर्शनों के बावजूद इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई कर्मियों को महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके समक्ष आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। सभा को संबोधित करते हुए वानी ने कहा कि सफाई कर्मी समाज के वास्तविक नायक और अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, जो प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर शहरों और कस्बों को स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाले कर्मचारियों को सम्मान और प्रोत्साहन मिलने के बजाय उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका मनोबल प्रभावित हुआ है।

उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की हड़ताल का असर अब पूरे भद्रवाह शहर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। पिछले कई दिनों से कूड़े-कचरे और गंदगी के ढेर जमा होने से शहर के विभिन्न हिस्सों में दुर्गंध फैल रही है, जिससे आम नागरिकों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, छह घायल

अनंतनाग, 17 जून(हि.स.)। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में पहलगाम के अरु इलाके में बुधवार को एक गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक कार शामिल थी। घटना के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। हादसे की जगह से दो शव बरामद किए गए जबकि घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले जाया गया।

मरने वालों में से एक की पहचान इमरान अहमद गनी के तौर पर हुई है जो गाड़ी चला रहा था। अधिकारियों ने बताया कि जेके 03सी-6737 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ी में सवार लोग अनंतनाग ज़िले के डायलगम के पेथबुग इलाके के रहने वाले थे।

दूसरे मृतक की पहचान और घायलों की हालत के बारे में अभी पुष्टि नहीं हो पाई थी। इस बीच पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की जांच चल रही है।

नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत जांच अधिकारियों के लिए दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू

जम्मू, 17 जून। 11 अप्रैल 2026 को शुरू किए गए 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर ने आज पुलिस ऑडिटोरियम, गुलशन ग्राउंड, जम्मू में जांच अधिकारियों के लिए दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) भीम सेन टूटी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नशे के खतरे से लड़ने के लिए कानून प्रवर्तन, गुणवत्तापूर्ण जांच, प्रभावी अभियोजन, पीड़ितों के पुनर्वास और जनभागीदारी सहित बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित जांच अधिकारी आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ होते हैं और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जम्मू-कठुआ-सांबा (जेकेएस) रेंज तथा उधमपुर-रियासी (यूआर) रेंज के कुल 120 जांच अधिकारी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य एनडीपीएस मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों की पेशेवर दक्षता बढ़ाना और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना है। 100 दिवसीय अभियान का लक्ष्य कानून प्रवर्तन, रोकथाम, जागरूकता, पुनर्वास और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ जोड़कर नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना, नशे के हॉटस्पॉट की पहचान करना तथा समाज के संवेदनशील वर्गों को जागरूक बनाना है। दो दिवसीय कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर और राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी की स्थिति, एनडीपीएस अधिनियम के कानूनी प्रावधान, एनडीपीएस मामलों की जांच और अभियोजन, नवीन तकनीकी प्रगति, फोरेंसिक एवं फिंगरप्रिंट तकनीकों का उपयोग, एनएएफआईएस प्रणाली तथा एफआईआर दर्ज होने से लेकर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने तक की जांच प्रक्रिया पर आधारित अध्ययन सत्र शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात, बाढ़ राहत समेत विभिन्न मुद्दे उठाए

जम्मू, 17 जून (हि.स.)। गुज्जर नगर जम्मू के मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू स्थित राजीव भवन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से मुलाकात कर समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमण भल्ला और जम्मू पूर्व विधानसभा प्रभारी सोहित शर्मा भी मौजूद रहे जिन्होंने इस बैठक का आयोजन किया।

प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र की कई लंबित समस्याओं को कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष रखा। विशेष रूप से उन्होंने पिछले वर्ष आई बाढ़ के दौरान हुए संपत्ति नुकसान के लिए अब तक राहत नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधियों ने कहा कि गुज्जर नगर क्षेत्र के प्रभावित परिवारों को अभी

तक कोई आर्थिक सहायता या राहत प्रदान नहीं की गई है जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराई जाए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तारिक हमीद कर्रा ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि कांग्रेस नेतृत्व इन मामलों को संबंधित विभागों और अधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाएगा। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करना कांग्रेस की प्राथमिकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से पार्टी की बैठकों और कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय भागीदारी निभाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों को मजबूत तरीके से उठाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक है।

प्रशासन ने अनियमितताओं के चलते प्राइवेट क्लिनिक को सील किया; स्थानीय लोगों ने गहन जांच की मांग की

मेंढर, 17 जून(हि.स.)। नियमों के उल्लंघन और गड़बड़ियों के आरोप में मेंढर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर पुंछ ज़िले के मेंढर शहर में डाक बंगले के सामने स्थित एक प्राइवेट मेडिकल सेंटर, एपेक्स हेल्थ केयर क्लिनिक को सील कर दिया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई क्लिनिक के निरीक्षण के दौरान मेंढर की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. ग़ज़ाला, मेंढर के एसएचओ , पुलिस की एक टीम और मेंढर के नायब तहसीलदार ने संयुक्त रूप से की। पत्रकारों से बात करते हुए बीएमओ ने बताया कि निरीक्षण के समय क्लिनिक में कोई क्वालिफाइड नेत्र विशेषज्ञ मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि सेंटर में केवल एक बीयूएमएस डॉक्टर काम करते हुए पाया गया जिसके बाद अधिकारियों ने संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की और आगे की जांच होने तक क्लिनिक को सील कर दिया। इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया और क्लिनिक के कामकाज की विस्तृत जांच की मांग की। कई स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खास मेडिकल सेवाओं के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया और उनसे पैसे ऐंठे गए। स्थानीय निवासियों ने कहा कि हमने बार-बार इस क्लिनिक के कामकाज को लेकर चिंता जताई है। इस बात का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच होनी चाहिए कि क्या मरीज़ों का इलाज बिना क्वालिफाइड विशेषज्ञों की मौजूदगी के किया जा रहा था। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और ज़िला प्रशासन से क्लिनिक के रिकॉर्ड, मंज़ूरी और मेडिकल प्रैक्टिस की जांच करने का भी आग्रह किया ताकि जवाबदेही तय की जा सके और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके।

U T OF JAMMU & KASHMIR
Office of the Superintendent Govt. Industrial Training Institute Bani.
Contact:-01921251973Website:- itibani.in

Subject: - Extension of Last Date for Online Admission for the session 2026-27/28 at Govt. ITI Bani.

S.No.	Name of the Trade	Whether NCVT/SCVT	Scheme	Prescribed Qualification	Duration of Course
1.	Computer Operator and Programming Assistant	NCVT	Normal	10th Pass	01 Year
2.	Plumber	NCVT	Normal	8th Pass	01 Year
3.	Sewing Technology	NCVT	Normal	8th Pass	01 Year
4.	Draughtsman Civil	NCVT	Normal	10th Pass	02 Years

In pursuance to the Directorate of Skill Development Department, J&K, Srinagar's Notice No. DSD/401/Trgs/2026/1018-1110 Dated:-15-06-2026, the last date for applying through online Admissions in various Trades of One Year/Two Yearsduration advertised by this Institute vide No:- ITI/BNI/2026-27/62-68, Dated:-29-05-2026 for the Academic Session 2026-27/28 is hereby further extended up to 30thJune, 2026.

DETAIL OF TRADES IN GOVT ITI BANI.
No: -ITI/BNI/2026-27/85-91 **Dated: -15-06-2026**

DIP/J-3885/26
Dtd: 17-6-2026

Sd/-
Superintendent
Govt. ITI Bani.

संपादकीय

ध्वस्त बाजार के कर्मचारियों का पुनर्वास किया जाए

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के निकट जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान सड़क को जाममुक्त बनाने के लिए आवश्यक था, क्योंकि यह बाजार कथित रूप से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान 30 से अधिक अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया और लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

निस्संदेह, जम्मू को पुनः सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आवश्यक हो गई हैं, क्योंकि अवैध अतिक्रमणों ने शहर की सुंदरता और स्वरूप को प्रभावित किया है। हालांकि जिन दुकानों को ध्वस्त किया गया, उनमें अधिकांश भोजनालय और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे, जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत थे। ऐसे में सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इन कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

अतिक्रमित भूमि पर बने प्रतिष्ठानों में कार्य करना कोई अवैध कार्य नहीं है, क्योंकि वहां काम करने वाले कर्मचारियों की इस अनधिकृत निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। विचारणीय तथ्य यह है कि इन दुकानों में कार्यरत अनेक कर्मचारी अपनी आजीविका चला रहे थे और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर रहे थे। इन प्रतिष्ठानों के ध्वस्तीकरण के बाद वे अचानक बेरोजगार हो गए हैं।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रति सरकार को विशेष संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में रोजगार प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में, जो 1990 के दशक से विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है और जहां बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार प्रभावित कर्मचारियों के लिए मासिक राहत पैकेज अथवा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराए, ताकि वे अपने परिवारों का भरण-पोषण कर सकें। इसके अतिरिक्त, उन्हें चल रही विकास परियोजनाओं में रोजगार उपलब्ध कराया जाए, कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि उनकी रोजगार क्षमता बढ़ सके तथा जो कर्मचारी अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण, सब्सिडी और उद्यमिता सहायता प्रदान की जाए।

इस प्रकार की पहलों के माध्यम से वे लोग, जो इस अभियान के कारण बेरोजगार हो गए हैं, अपने जीवन को पुनः पटरी पर ला सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस कठिन समय में उन प्रभावित कर्मचारियों की सहायता के लिए आगे आए, जिन्होंने बिना किसी गलती के अपनी आजीविका खो दी है।

सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती और प्रभावित समुदाय को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस ध्वस्तीकरण अभियान ने एक ही रात में उनकी रोजी-रोटी छीन ली है और उन्हें असुरक्षित स्थिति में ला खड़ा किया है।

सत्ता और प्रशासन में बैठे लोगों का दायित्व है कि वे प्रभावित कर्मचारियों के जीवन को पुनः संवारने में मदद करें और उन्हें सम्मान तथा आत्मगौरव के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। इन कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने और ध्वस्तीकरण अभियान के सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

वेतन से आगे- विकसित भारत के लिए कुशल कार्यबल की तैयारी

यह समय उनके नियोक्ता के लिए भी अहम था, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई थी और उसने अपने विस्तार के तहत रवि को काम पर रखा था। पीएम-वीबीआरवाईके भाग क्रमें प्रावधान है कि जो नियोक्ता अपनी मौजूदा बेसलाइन से ज़्यादा रोज़गार पैदा करते हैं, उन्हें हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपये तक का सरकारी योगदान मिलता है। यह योगदान अलग-अलग क्षेत्रों में दो साल तक और विनिर्माण क्षेत्र में चार साल तक मिलता है। यह योगदान उस शुरुआती लागत का कुछ हिस्सा कवर करता है, जो किसी कंपनी को नए कर्मचारी को रखने पर उठानी पड़ती है, खासकर तब जब ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण चल रहा होता है और बिना किसी पिछले औपचारिक अनुभव वाला कर्मचारी, धीरे-धीरे कंपनी के लिए लाभप्रद हो रहा होता है।

- डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम

कोयंबटूर में काम करने वाले युवा रवि को, जो एक छोटी विनिर्माणइकाई में अपनी पहली औपचारिक नौकरी के छह महीने पूरे कर चुके हैं औरहाल ही में अपनी मासिक तनख्वाह के अलावा उन्हेंबैंक खाते में 7,500 रुपये मिले। लगातार छह महीने की नौकरी पूरी होने के बाद यह रकम अपने आप जारी कर दी गई। इससे पहले उनका परिवार सिर्फ़ अनौपचारिककाम करता था, जिसमें कोई अनुबंध, भविष्य निधि में योगदान या नौकरी का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था।यह पहला मौका था, जब उनकी नौकरी को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया और उन्हें इस तरह का लाभ मिला।

रवि को मिली यह धनराशिप्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के भाग के तहत मिली पहली किस्त है। इस योजना को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री के रोज़गार और कौशल पैकेजके हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। इस प्रावधान के तहत, ईपीएफओ में पंजीकृत कंपनियों में पहली बार नौकरी पाने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनकी मासिक कमाई 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें 15,000 रुपये तक का नकद प्रोत्साहन मिलता है। यह रकम दो किस्तों में दी जाती है- पहली किस्त लगातार छह महीने की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त बारह महीने के बाद। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी को ईपीएफओ पोर्टल के ज़रिए वित्तीय साक्षरता का कोर्स पूरा करना होगा और यह राशि बचत के एक साधन में जमा की जाएगी, ताकि कर्मचारी को एक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। रवि के लिए, ये छह महीने सिर्फ़ योग्यता हासिल करने का समय नहीं थे। ये वो वक्त था, जिसमें उन्होंने अपने काम की जगह को समझा, अपने काम से जुड़ी बुनियादी कौशल और योग्यता सीखी और अपने लिए रोज़गार का एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, जो पहले कभी नहीं था।

यह समय उनके नियोक्ता के लिए भी अहम था, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई थी और उसने अपने विस्तार के तहत रवि को काम पर रखा था। पीएम-वीबीआरवाईके भाग क्रमें प्रावधान है कि जो नियोक्ता अपनी मौजूदा बेसलाइन से ज़्यादा रोज़गार पैदा करते हैं, उन्हें हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपये तक का सरकारी योगदान मिलता है। यह योगदान अलग-अलग क्षेत्रों में दो साल तक और विनिर्माण क्षेत्र में चार साल तक मिलता है। यह योगदान उस शुरुआती लागत का कुछ हिस्सा कवर करता है, जो किसी कंपनी को नए कर्मचारी को रखने पर उठानी पड़ती है, खासकर तब जब ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण चल रहा होता है और बिना किसी पिछले औपचारिक अनुभव वाला कर्मचारी, धीरे-धीरे कंपनी के लिए लाभप्रद हो रहा होता है। इस शुरुआती लागत को कम करकेयह प्रावधान, योजना का दायरा रवि जैसे लोगों को काम पर रखने वाले छोटे व्यवसायों तक बढ़ाता है। उसकी जैसी विनिर्माणइकाईयों के लिए, चार साल की अवधि, जो सामान्य अवधि से दोगुनी है, कंपनियों को ऑटोमेशन में निवेश के साथ-साथ अपने कार्यबल का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

भारत की जनसांख्यिकीय व्यवस्था को देखते हुए, युवा और बढ़ताकार्यबल 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए रोज़गार-आधारित विकास के ज़रिए आर्थिक विकास को रफ्तार देने का एक मौका देता है। कार्यबल में शामिल होने वाले नए लोग किस सीमा तक औपचारिक रोज़गार में आते हैं, जहाँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत सुरक्षा मिलती है, यह इस बात पर भी असर डालेगा कि परिवारों और समुदायों में विकास का लाभ कैसे मिलता है। पीएम-वीबीआरवाईका मकसद स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत तक के सफ़र को मज़बूत करना है और दो साल में 3.5 करोड़ से ज़्यादा औपचारिक नौकरियाँ पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देना है।

इस योजना की शुरूआत से, 60 लाख नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से 43.26 लाख (लगभग 71ब्र) 18 से 30 साल की उम्र के हैंऔर 18.04 लाख (लगभग 30ब्र) महिलाएं हैं, जो पहली बार औपचारिक रोज़गार से जुड़ी हैं। ये कर्मचारी विशेषसेवाओं, इंजीनियरिंग, व्यापार, विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो दिखाता है कि कई तरह के औपचारिक संस्थानों में इसे अपनाया गया है।

सिर्फ़ प्रोत्साहन राशि के अलावा, पीएम-वीबीआरवाई से रवि को एक ईपीएफओ खाता और एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला है। इससे वह एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, जो भविष्य निधि योगदान, बीमा सुरक्षा और कानूनी रोज़गार लाभ भी देता है। उनके जैसे पहली बार औपचारिक रोज़गार पाने वाले कई लोगों के लिए, यह सामाजिक सुरक्षा कवरेज और एक व्यवस्थित रोज़गार से जुड़ने का एक बेहतर मौका है।

लगातार छह महीने तक नौकरी करने की शर्त का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना के तहत बनी नौकरियां असल करियर की नींव बनें। लंबे समय तक औपचारिक रोज़गार से कई क्षेत्रों में नौकरियों में काम आने वाला कौशल विकसित होता हैं, पेशेवर तौर-तरीके सीखने को मिलते हैं और भविष्य में नौकरी पाने की क्षमता भी मज़बूत होती है। इससे मिलने वाले फ़ायदे योजना के तहत मिलने वाली मदद की अवधि के बाद भी बने रहते हैं।

रोज़गार के मौके पैदा करना एक अहम नीतिगत लक्ष्य है। उतना ही ज़रूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि रवि जैसे कर्मचारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाए रख सकें, जहाँ रोज़गार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा कवरेज और संस्थागत सुरक्षा भी मिलती है। जैसे-जैसे ज़्यादा युवा कर्मचारीऔपचारिक नौकरियों में छह महीने, एक साल और उससे ज़्यादा समय बिताते हैं, कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आता है और छोटे संस्थान भी औपचारिक तरीके से लोगों को काम पर रखने की प्रक्रिया अपनाते हैं। इस योजना के तहत 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां मिलने का अनुमान हैऔर औपचारिक अर्थव्यवस्था का यह धीरे-धीरे बढ़ता दायरा ही वह बदलाव है, जिसे तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए पीएम-वीबीआरवाईको लाया गया है।

(लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं)

आकांक्षाओं का गणित- भारत में रोजगार का सवाल अब स्थिरता पर क्यों निर्भर है

डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन

जब 1954 में सर आर्थर लुईस ने गरीब अर्थव्यवस्थाओं के अमीर बनने की परिघटना को समझाने का काम शुरू किया, तो उन्होंने विकास की मुख्य प्रक्रिया को पूंजीके संचयके रूप में नहीं बल्कि कामगारों के जीवन-निर्वाह वाली खेती से हटकर अधिक कमाई वाले उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों की ओर मुड़ने के तौर पर पहचाना। उनका यह अनुमान बिल्कुल ही सही था कि यही बदलाव देर से औद्योगीकरण करने वाले हर देश का भविष्य तय करेगा।आज भारत ठीक इसी मोड़ पर खड़ा हैऔर नीति-निर्माताओं के सामने सवाल पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध कराने भर का नहीं ह

ै। बल्कि, उनके सामने इससे भीअधिक अहम सवाल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी नौकरियां पैदा करने की स्थिति में है या नहींजो पर्याप्त तादाद में हों, औपचारिक हों और एक युवा कामगार को जीवन भर बढ़ती उत्पादकता एवं सुरक्षा दे सकने लायक टिकाऊ हों।

इस जिम्मेदारी के भार को काफी सटीकता से बताया जा सकता है।'आर्थिक समीक्षा 2023-24'ने 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे'और आबादी से जुड़े अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि इस दशक की बाकी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को हर वर्ष लगभग 78.5 लाख गैर-कृषि नौकरियां सृजितकरनी होंगी। यह आंकड़ा दो बढ़ते दबावों का नतीजा है- पहला, कामकाज के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ने के साथ श्रमशक्ति में हो रही लगातार बढ़ोतरी; और दूसरा, संरचनात्मक बदलाव के कारण खेती से बाहर आने वालेकामगार।रोजगार में खेती की हिस्सेदारी अभी भी लगभग 46 प्रतिशत है। वर्ष 2047 तकइस हिस्सेदारी के घटकर एक-चौथाई तक आ जाने की संभावना है।

जुलाई 2025 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई और उसके अगले महीने से शुरू हुई 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना'उस अंतर को पाटने की अब तक की सबसे सोची-समझी कोशिश है। इस योजना के तहत, जुलाई 2027 तक की दो वर्षों की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित करने हेतु'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ'के जरिए 99,446 करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं।ईपीएफओमें पंजीकृत किसी कंपनी में पहली बार शामिल होने वाला और महीने में एक लाख रुपये से कम कमाने वाला कामगार, दो किस्तों में कुल 15,000 रुपये तक पाने का हकदार बन जाता है। दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रमफाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करने पर और बचत (सेविंग्स) के तौर पर मिलती है।

वहीं, निर्धारित आधार-रेखा (बेसलाइन) से अधिक लोगों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं को हर नए कामगार के लिए महीने में 3,000 रुपये तक मिलते हैं। ये शर्तें कुछ इस तरह तय की गई हैं कि छोटी कंपनियां भी इसके दायरे से बाहर हो जाने के बजाय इसमें शामिल हो सकें।

यह योजना भर्तीसंबंधी सब्सिडी वाले आम व निराशाजनक तरीकों से इसलिए अलग और बेहतर है क्योंकि इसमें पहला लाभ मिलने से पहले छह महीने तक लगातार नौकरी करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार काम करने वाले को नौकरी पर रखने का लाभ तभी मिलता है जब वह कर्मचारी काम में कुशल बन जाए और टिका रहे। यह शर्त शुरुआती भर्ती को एक पक्की प्रतिबद्धता में बदल देती है, जिससे नियोक्ता को प्रशिक्षण की लागत वसूलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और कर्मचारी को भी उतने महीने मिल जाते हैं जिनमें वह असली हुनर सीख सके और भरोसेमंद रिकॉर्ड बना सके। इस तरह, यह योजनाकेवल नौकरी देने के लिए नहींबल्कि कर्मचारी को बनाए रखने की अपेक्षाकृत अधिककठिन प्रक्रिया के लिए पुरस्कृत करती हैऔर इसके बाद कर्मचारी के पास रोजगार क्षमता एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्डहोता है जिसका वह कहीं भी सदुपयोग कर सकता है।

इस योजना का सबसे अधिक झुकाव मैन्यूफैक्चरिंग की ओर है, जहां नियोक्ता को मिलने वाला प्रोत्साहन दो वर्ष के बजाय चार वर्ष तक मिलता है। समय-सीमा को दोगुनी करने का यहनिर्णयऔद्योगिक क्षमता तैयार होने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखकर लिया गया है। साथ ही, इससे निर्माता (मैन्यूफैक्चरर) समय से पहले स्वचालित व्यवस्था (ऑटोमेशन) लाकर कामगारों को हटाने के बजाय श्रमशक्ति बढ़ाने की ओर प्रेरित होते हैं। अहम बात यह है कि सरकार ने इसे देश कोवैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग केन्द्रबनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से जरूरी माना है। ईपीएफओके जरिए, हर नए कामगार को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का पहली बार अहसास होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत कम कामगारों को यह सुरक्षा मिल पाती है। इस योजना के शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं।इसकेशुरू होने के बाद से लगभग 60 लाख नए कर्मचारी नामांकित हुए हैं।इनमें से अधिकतर 30 वर्ष से कम आयु के हैं और 18 लाख से अधिकमहिलाएं हैं। वहीं, लगभग 1.77 लाख प्रतिष्ठानों ने 66 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।

इन प्रतिष्ठानों में कई ऐसी छोटी कंपनियां शामिलहैं,जहां लंबे समय से अनौपचारिक काम का बोलबाला रहा है।हालांकि, एक अच्छी शुरुआत को पूरी तरह से सफल बदलाव मान लेना नासमझी होगी। इस योजना में धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों को बाहर रखने, हर छह महीने में इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न के जरिए यह सुनिश्चित करना कि नौकरी सिर्फ कागजों के बजाय असल में बनी हुई हैऔर भुगतान की स्वचालित प्रणाली जैसी कई अच्छी बातें हैं। ये सभी खूबियां इस बात को दर्शाती हैं कि योजनाकारों को इस बात का अहसास है कि ऐसी योजना में उन भर्तियों को लाभ नहीं मिलना चाहिए जो अन्यथाभी हो जातीं। इसकी असली सफलता पहले वर्ष में नामांकित लोगों के आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से पता चलेगी कि वे नौकरियां उस प्रोत्साहनके समाप्त होने के बाद भी बनी रहती हैं या नहीं और इससे पैदा होने वाली मांग को पूरा करने के लिए काम के लायक युवा मौजूद हैं या नहीं। इसीलिए, इस योजना की सफलता कौशल को सिखाने में किए जा रहे निवेश से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।

यह याद रखना ज़रूरी है कि बेरोजगारी सिर्फ आमदनी से ही वंचित नहीं करती, बल्कि यह लोगों के हुनर, आत्म-सम्मान और समाज में उनकी हैसियत को भी कमजोर करती है। वोल्टेयर ने भी यही बात कही थी जब उन्होंने कैंडिड के जरिए यह निष्कर्ष दिया था कि काम करने से तीन बड़ी समस्याएं - बोरियत, बुराई और अभाव - दूर रहती हैं। इस तरह की योजना की अहमियत इसलिए है क्योंकि यह रोजगार के सही और संपूर्ण मतलब को समझती है।यह औपचारिक नौकरी को सिर्फ गिनती के आंकड़े के तौर पर नहीं, बल्कि कामकाजी जीवन की पहली सुरक्षित सीढ़ी के तौर पर देखती है। अबजबकि भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है, तो चुनौती इस बात की है कि इस योजना में दिखाई गई धैर्य की भावना को बनाए रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि युवाओं को सार्थक रोजगार, जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परियोजना के केन्द्र में रखा है, कुछ समय के प्रोत्साहन तक सीमित रहने के बजाय एक पूरी पीढ़ी के लिए टिकाऊ, उत्पादक और सम्मानजनक काम के रूप में मिले।

(लेखक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं)

आईआईटी की दहलीज पर बेटियों की रिकॉर्ड दस्तक

-प्रतिभा कुशवाहा

हाल ही में जेईई एडवांस्ड-2026 परीक्षा में लड़कियों की शानदार सफलता की जो खबरें आईं हैं, उसने एसटीईएम (स्टेम) यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं के भविष्य की तस्वीर साफ होने लगी है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में आधी आबादी के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है

। देश में इंजीनियरिंग यानी आईआईटी में शिक्षा एक पुरूष प्रधान क्षेत्र बना हुआ है। हमारे घरों में जो बच्चियों की शिक्षा को लेकर मुखर हैं, वे भी अपने बेटों को इंजीनियर और बेटियों को डाक्टर बनाना पहली प्राथमिकता में रखते हैं। फिर भी यह सफलता हमारे घरों की बदलती सोच और आर्थिक व्यवस्था के कुछ सुराग तो दे ही रहा है।

चार जून को प्रकाशित हुए अखबारों में प्रमुख रूप से इस खबर को प्रकाशित किया कि इस बार जेईई एडवांस्ड-2026 परीक्षा में पहली बार लगभग 10,000 लड़कियों ने पास की है। इस परीक्षा में कुल 56,880 अभ्यर्थी सफल हुए जिनमें से 10,107 सफल लड़कियां शामिल हैं। इन आकड़ों में लगभग चार अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी लड़की है। यह ऐतिहासिक सफलता केवल परीक्षा परिणामों का आंकड़ा मात्र नहीं है, वरन हमारे समाज में शिक्षा, अवसर और लैंगिक समानता के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का संकेत भी है। यह सफलता महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में एक 'पुश' के तौर पर देखा जा रहा है।

आज एआई, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और नई तकनीकों ने पूरे समाज, संस्कृति और अर्थिकीय को अपने आगोश में ले रखा है, इससे आधी आबादी का दूर रहना एक बहुत बड़े सामाजिक असंतुलन के रूप में सामने आ सकता है। ऐसे में जेईई एडवांस्ड-2026 के परिणाम भविष्य में देश की नई तस्वीर का निर्माण कर सकते हैं।

हालांकि अभी भी शीर्ष रैंकों और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। मात्र इस तरह की और भी सफलताओं से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

महिलाओं के जीवन में इतने पड़ाव आते हैं कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में पढ़ने-लिखने के बाद भी अपना योगदान देने से वे वंचित रह जाती हैं।

आर्थिक तौर पर यह पढ़ाई महंगी होती है, देश इन क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह की आर्थिक सहायता भी देता है। अगर कार्यक्षेत्र तक महिलाएं आगे नहीं आ सकेगी, तो नुकसान हमारे समाज और देश का ही ज्यादा होगा।

जनवरी, 2026 को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश में उच्च शिक्षा स्तर स्टेम विषयों में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी 43 फीसदी है।

इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुसंधान और विकास सांख्यिकी रिपोर्ट-2023 के अनुसार देश में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में स्टेम पेशेवरों के रूप में कुल महिला कार्यबल की हिस्सेदारी 18.6 फीसदी है।

इनमें से 45.8 फीसदी सरकारी संस्थानों में, 27.6 फीसदी उच्च शिक्षा क्षेत्र में और 26.5 फीसदी औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से भी पता चल रहा है कि जितनी महिलाएं स्टेम विषयों को लेकर अपना करियर बनाने का पथ चुन रही हैं, उतनी महिलाओं कार्यक्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं।

यूनेस्को का अपनी रिपोर्ट में मानना है कि भारत में एसटीईएम ग्रेजुएट में महिलाओं की भागीदारी 43 फीसदी है, जबकि इन क्षेत्रों में उनकी नौकरियों में भागीदारी मात्र 14 फीसदी है। तो प्रश्न उठता है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पढ़ी हुई महिलाएं गुम कहां हो जाती हैं? क्या समाज और संस्कृति की गहरी जड़ें जमा चुकी परंपराएं और मान्यतागत भेदभाव कहीं न कहीं इन क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार में बाधा बन जाते हैं। पारंपरिक जेंडर भूमिकाएं इस क्षेत्र में करियर बना रही महिलाओं को बहुत हद तक हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र महिलाओं से अधिक समय और प्रतिबद्धता की मांग करता है। कई परिवार चाहते हैं कि उनकी बहु और बेटी इस क्षेत्र में पढ़े तो, पर रिसर्च की जगह वह टीचिंग जैसा स्थिर और स्मूथ करियर ऑप्शन चुनें।

जेंडर सेंसटिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी कार्यस्थल पर महिलाओं को यह क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं। यही स्टीरियोटाइप सोच इंजीनियरिंग और फिजिक्स को पुरुष प्रधान क्षेत्र बना देती है।

सिस्टम में इतने लूपहोल होने के बावजूद यदि इन क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता की बात की जाए, तो 2013 का मंगल मिशन और 2019 का चंद्रयान-2 मिशन अपनी एक अलग ही ऐतिहासिक उपलब्धि से हमें गौरवान्वित करता है। चंद्रयान-2 मिशन की कमान संभालने वाली दो महिला वैज्ञानिक ऋतु करीधल और एम. वनिता को कौन भूल सकता है। इसरो की वैज्ञानिक ऋतु करीधल चंद्रयान-2 मिशन की डायरेक्टर थीं और एम. वनीता इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इनकी अथक मेहनत का फल है कि आज देश अंतरिक्ष क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट कर सका। इससे पहले 2013 में मंगल मिशन की सफलता का जश्न देश मना चुका है। इस मिशन में आठ महिला वैज्ञानिकों ने अपनी खास भूमिका निभाई थी। इस विषय को आधार बनाकर एक फिल्म 'मिशन मंगल' भी बन चुकी है।

चंद्रयान-2 मिशन में इन दो महिला वैज्ञानिक के अलावा और भी महिला वैज्ञानिकों का साथ मिला।

इस प्रोजेक्ट में 30 फीसदी महिला वैज्ञानिकों की अथक परिश्रम शामिल है। चंद्रयान-2 मिशन में मौमिता दत्ता, नंदिनी हरिनाथ, एन. वलारमथी, मीनल संपथ, कीर्ति फौजदार और टेसी थॉमस जैसी दूसरी महिला वैज्ञानिक शामिल हैं। इस उपलब्धि को बांटते हुए इसरो के चेयरमैन के. सिवन ने उस समय मीडिया से कहा था कि हम पुरुष और महिला वैज्ञानिकों में अंतर नहीं समझते हैं। जो भी सक्षम होता है, उसे बेहतरीन काम सौंपा जाता है। यहीं सवाल उठता है तो फिर महिलाओं की इस सक्षमता को 'ब्रेक' कौन लगा जाता है?

(लेखिका, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

फीफा वर्ल्ड कप: नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया, हालैंड बने जीत के नायक

एजेंसी

बोस्टन । नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। बोस्टन स्टेडियम में ग्रुप आई के मुकाबले में नॉर्वे ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इराक को 4-1 से हराया। नॉर्वे की तरफ से फीफा विश्व कप में अपना डेब्यू कर रहे एर्लिंग हालैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो गोल किए, जबकि लियो ओस्टिगार्ड ने भी एक गोल दागा। यह मुकाबला इसलिए भी खास था, क्योंकि नॉर्वे और इराक दोनों ही लंबे समय बाद विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर लौटे थे। मैच की शुरुआत से ही नॉर्वे ने आक्रामक खेल दिखाया। 14वें मिनट में गोलकीपर ओरजान नाइलैंड की शुरुआत किए गए मूव पर डेविड मोलर वोल्फ ने बाएं छोर से शानदार क्रॉस दिया, जिसे हालैंड ने गोल में बदलकर नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिला दी। इस मैच में 35 साल और 279 दिन की उम्र में नाइलैंड नॉर्वे के लिए विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए। इराक ने भी मैच में जल्द ही वापसी की और दस मिनट बाद ही इस टूर्नामेंट का अपना पहला गोल दागा। टीम के अनुभवी फॉरवर्ड खिलाड़ी आयमन हुसैन विश्व कप में गोल करने वाले महज दूसरे इराकी खिलाड़ी बने। आमिर अल-अम्मारी के बेहतरीन क्रॉस पर शानदार हेडर मारते हुए आयमन ने गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया।

फीफा वर्ल्ड कप: पहले ही मैच में एमबाप्पे का कमाल, मेसी का तोड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली । फ्रांस के स्टार खिलाड़ी काइलियन एमबाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। एमबाप्पे ने दो गोल करते हुए फ्रांस को सेनेगल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 3-1 से जीत दिलाई। एमबाप्पे ने लियोनेल मेसी को भी खास मामले में पीछे छोड़ दिया है। काइलियन एमबाप्पे फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। एमबाप्पे इस मेगा इवेंट में अब तक 15 मुकाबलों में 14 गोल कर चुके हैं। एमबाप्पे ने मेसी को पीछे छोड़ दिया है। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी ने विश्व कप में खेले 26 मुकाबलों में 13 गोल किए हैं। इसके साथ ही एमबाप्पे फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस की तरफ से सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज के नाम दर्ज है, जिन्होंने कुल 24 मुकाबलों में 16 गोल किए हैं। वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ब्राजील के स्टार फुटबॉलर रहे रोनाल्डो का नाम है। रोनाल्डो ने 19 मुकाबलों में 15 गोल किए हैं। सेनेगल के खिलाफ किए गए दमदार प्रदर्शन को अगर एमबाप्पे पूरे विश्व कप में कायम रखने में सफल रहे, तो वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं।

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ की वापसी

एंटीगा। श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ की चोट के बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। वहीं विकेटकीपर-बल्लेबाज जोशुआ डा सिल्वा और अमीर जंगू को भी दोबारा मौका मिला है। अल्जारी और शमार पिछले वर्ष भारत और न्यूजीलैंड दौरे के दौरान चोट के कारण टीम से बाहर थे। दोनों ने आखिरी बार 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबला खेला था। उनकी वापसी से वेस्टइंडीज का तेज गेंदबाजी आक्रमण मजबूत हुआ है, जिसमें केमार रोच और जेडन सील्स भी शामिल हैं। विकेटकीपर की भूमिका में जोशुआ डा सिल्वा की वापसी हुई है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने हालिया वेस्टइंडीज चैम्पियनशिप में सात पारियों में 413 रन बनाए और प्रतियोगिता के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। वहीं पिछले दौरे में विकेटकीपिंग करने वाले तेविन इमलाच को मुख्य टीम में जगह नहीं मिली है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ 18 से 21 जून तक होने वाले चार दिवसीय अभ्यास मैच के लिए वेस्टइंडीज चयन एकादश का कप्तान बनाया गया है।

विंबलडन में फिर साथ उतरेंगी विलियम्स बहनें, महिला युगल में सेरेना और वीनस को मिला वाइल्ड कार्ड

लंदन। टेनिस जगत की दिग्गज बहनें सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स एक बार फिर विंबलडन के कोर्ट पर साथ दिखाई देंगी। ऑल इंग्लैंड क्लब ने महिला युगल प्रतियोगिता के लिए दोनों को वाइल्ड कार्ड प्रदान किया है। यह फैसला ग्रैंड स्लैम के शुरू होने से करीब दो सप्ताह पहले ऐसे समय लिया गया है, जब सेरेना ने लगभग चार साल बाद पेशेवर टेनिस में वापसी की है। 44 वर्षीय सेरेना ने पिछले सप्ताह लंदन में क्वींस क्लब चैंपियनशिप से वापसी की थी, जबकि वीनस सीमित कार्यक्रम के साथ लगातार खेल रही हैं और बुधवार को 46 वर्ष की हो जाएंगी। विलियम्स बहनें टेनिस इतिहास की सबसे सफल महिला युगल जोड़ियों में गिनी जाती हैं। दोनों ने साथ मिलकर कुल 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं, जिनमें विंबलडन के छह खिताब शामिल हैं। उन्होंने पहला विंबलडन खिताब वर्ष 2000 में जीता था, जबकि ऑल इंग्लैंड क्लब में उनकी आखिरी जीत वर्ष 2016 में आई थी। सेरेना ने वापसी के दौरान क्वींस क्लब में कनाडा की विक्टोरिया मबोको के साथ अपना पहला युगल मुकाबला जीतकर शानदार शुरुआत की थी। हालांकि बाद में मबोको के घुटने में चोट लगने के कारण दोनों को प्रतियोगिता से हटना पड़ा।

फीफा वर्ल्ड कप: ऑस्ट्रिया ने जीत के साथ किया आगाज, जॉर्डन को 3-1 से हराया

एजेंसी

सांता क्लारा । फीफा वर्ल्ड कप में 28 साल में अपना पहला मैच खेलने उतरी ऑस्ट्रिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जॉर्डन को रोमांचक मुकाबले में 3-1 से हराया। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू करने वाली जॉर्डन की टीम ने ऑस्ट्रिया को कड़ी टक्कर देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन टीम को अपनी गलतियों के कारण खामियाजा भुगतना पड़ा। मैच की शुरुआत में ऑस्ट्रिया को जॉर्डन की तरफ से कड़ी चुनौती मिली। मैच के दूसरे मिनट में जॉर्डन के कप्तान एहसान हद्दाद ने पहला मौका बनाया, लेकिन उनका शॉट साइड नेटिंग में चला गया। इसके बाद ओदेह फखौरी ने भी दूर से शानदार प्रयास किया, जिसे ऑस्ट्रिया के गोलकीपर अलेक्जेंडर श्लेगर ने

बेहतरीन बचाव करते हुए गोल में जाने से रोक दिया। शुरुआती दबाव झेलने के बाद ऑस्ट्रिया ने 20वें मिनट में मैच का पहला गोल करते हुए बढ़त हासिल की। रोमानो श्मिड ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया और टीम को 1-0 से आगे कर दिया।

पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद जॉर्डन की टीम ने लगातार लड़ाई जारी रखी। दूसरे हाफ की शुरुआत के कुछ ही मिनट बाद अली ओलवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने ऑस्ट्रियाई डिफेंडरों को छकाते हुए बेहतरीन गोल किया। ओलवान वर्ल्ड कप में गोल करने वाले जॉर्डन के पहले खिलाड़ी बने। इस गोल से स्कोर 1-1 हो गया।

इसके बाद दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के प्रयास जारी रहे। मैच के 67वें मिनट में ऑस्ट्रिया ने एक बार फिर से बढ़त हासिल की, लेकिन वीएआर में बिल्ड-अप के दौरान हैंडबॉल पाए जाने के कारण गोल को रद्द कर दिया गया। हालांकि, इसके कुछ मिनट बाद ही जॉर्डन के डिफेंडर याजान अल अरब ने दुर्भाग्यवश अपने ही गोलपोस्ट में हेडर मार दिया, जिससे ऑस्ट्रिया 2-1 से आगे हो गया। मैच के अंतिम क्षणों में जॉर्डन ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन इंजरी टाइम में ऑस्ट्रिया को पेनल्टी मिल गई। अनुभवी स्ट्राइकर मार्को अर्नौटोविक ने कोई गलती नहीं की और पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम की 3-1 से जीत सुनिश्चित कर दी।

हमारे पास इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सबसे अच्छा मौका: हैरी केन

एजेंसी

आर्लिंगटन । इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन का मानना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में टीम के पास ट्रॉफी को अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा। बायर्न म्यूनिख के लिए 51 मुकाबलों में 61 गोल करने वाले शानदार सीजन के बाद स्ट्राइकर को भरोसा है कि वह अपने करियर की सबसे अच्छी फॉर्म को जारी रखने और इंग्लैंड को टूर्नामेंट में आगे तक ले जाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। इंग्लैंड फीफा विश्व कप में अपने अभियान का आगाज क्रोएशिया के खिलाफ गुरुवार को करेगा। मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए 32 साल के खिलाड़ी ने कहा, 'मैं निजी तौर पर कहूंगा कि यह मानसिक और शारीरिक तौर पर मेरा अब तक का सबसे अच्छा सीजन है। मेरे लिए सीजन का अंत बहुत अच्छा रहा। शारीरिक तौर पर मैं खुद को बहुत अच्छी शेप में महसूस कर रहा हूं।' 'अपने करियर के लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है जो आपके हिसाब से हों और सही समय पर सही जगह पर हों और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के लिए ऐसा ही हुआ है। मेरे हिसाब से एक टीम के तौर पर हमारे पास फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सबसे अच्छा मौका होगा। मुझे लगता है कि हर कोई अच्छी शुरुआत करने और यह साबित करने के लिए बेताब है कि हमारे पास इस टूर्नामेंट में आगे तक जाने की काबिलियत है। ' हैरी केन इंग्लैंड के अब तक के सबसे सफल स्ट्राइकरों में से एक हैं। वह इंग्लैंड के लिए ऑल-टाइम रिकॉर्ड गोलस्कोरर हैं और इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा अपीयरेंस (मैच खेलने) की सूची में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।

ईरान के कोच ने फीफा, अमेरिका पर साधा निशाना, कहा- हमें तुरंत जाने के लिए कहा गया

एजेंसी

लॉस एंजिल्स । ईरान के हेड कोच आमिर घालेनोई ने फीफा विश्व कप ग्रुप जी के पहले मैच में न्यूजीलैंड के साथ 2-2 से ड्रॉ होने के बाद अपनी टीम के यात्रा योजना में अचानक हुए बदलाव पर निराशा जताई। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में घालेनोई ने कहा, 'उनकी टीम को अचानक बताया गया कि उन्हें लॉस एंजिल्स में मैच के तुरंत बाद मेक्सिको लौटना होगा। टीम को पहले बताया गया था कि वे मंगलवार लंच तक अमेरिका में रह सकती हैं, लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ, ट्रिप प्लान बदल गया।' घालेनोई ने कहा, 'मैच के बाद उन्होंने कहा कि हमें तुरंत जाना होगा। हमें प्लेन में बैठकर तिजुआना में अपने कैंप में लौटने के लिए कहा गया है, और हम इससे परेशान हैं। वे हमें जल्दी वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वे हालात को और मुश्किल बना रहे हैं और मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपना श्रेष्ठ करने से रोकने नहीं देंगे। ' कोच ने यह भी दावा किया कि टूर्नामेंट की

तैयारी के दौरान ईरान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा, 'हमें मैच से दो रात पहले पहुंचना था, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी। हमें आज रात यहीं रुकना था और लंच टाइम पर लौटना था। मुझे लगता है कि हमारी टीम पूरे विश्व कप में सबसे ज्यादा परेशान है। हमारा फेडरेशन यहां नहीं है, हमारा मीडिया यहां नहीं है, हमारा मैनेजमेंट यहां नहीं है। '

ईरान के स्ट्राइकर मेहदी तारेमी ने हालात को बहुत बुरा मानते हुए कहा, 'यह खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए बहुत चिंता की बात है। हम बस इस हालात से थक चुके हैं। यह बहुत बुरा है, और इसका असर हमारी टीम पर पड़ता है। '

वर्ल्ड कप में ईरान का शामिल होना अनिश्चितता की वजह से खराब हुआ है, जो मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा है। इस बीच, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद ईरान टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात की। ईरान की यात्रा से जुड़ी चिंताएं ग्रुप स्टेज में भी जारी रह सकती हैं। उनका अगला ग्रुप जी मैच बेल्जियम के खिलाफ रविवार को सोफी स्टेडियम में होना है।

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप: निलाक्षिका-कौशानी की तूफानी पारी, न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका की 5 विकेट से जीत

एजेंसी

साउथेम्प्टन। श्रीलंका ने द रोज बाउल में खेले गए विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 7वें मैच में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ 'ग्रुप-बी' में मौजूद श्रीलंका ने जीत का खाता खोल लिया है, जबकि न्यूजीलैंड को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 150 रन बनाए। इस टीम को महज 4 रन पर इसाबेल गेज (4) के रूप में पहला झटका लगा गया था। यहां से कप्तान अमेलिया केर ने जॉर्जिया प्लिम्मर के साथ दूसरे विकेट के लिए 46 गेंदों में 49 रन जोड़कर पारी को संभाला। प्लिम्मर 22 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद केर ने सोफी डिवाइन के साथ तीसरे विकेट के लिए 26 गेंदों में 43 रन जुटाए। केर ने 36 गेंदों में 45 रन बनाए। उनकी इस पारी में 5 चौके शामिल रहे। इसके बाद सोफी डिवाइन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 30 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 45 रन जुटाए, जबकि मैडी ग्रीन 18 रन बनाकर नाबाद रहीं। विपक्षी खेमे से

काशवी दिलहारी ने 2 हासिल किए, जबकि मिताली अयोध्या, सुगंधिका कुमारी, चामरी अट्टापट्टू और निमाशा मीपेज को 1-1 विकेट हाथ लगा। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 19.4 ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान चामरी अट्टापट्टू ने विश्मी गुणारत्ने (17) के साथ 5.5 ओवरों में 45 रन की साझेदारी की। अट्टापट्टू 19 गेंदों में 1 छक्के और 4 चौकों के साथ 27 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। आलम ये रहा कि 8.3 ओवरों में 55 के स्कोर तक श्रीलंका ने अपने 4 विकेट खो दिए थे। यहां से काशवी दिलहारी ने निलाक्षिका सिल्वा के साथ 39 गेंदों में 49 रन जुटाए। काशवी टीम के खाते में 17 रन का योगदान देकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद निलाक्षिका ने कौशानी नुथ्यंगना के साथ 28 गेंदों में 48 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई। न्यूजीलैंड की तरफ से नेंसी पटेल ने 23 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि ब्री इलिंग को 1 विकेट हाथ लगा।

न्यूजीलैंड ने किया 2026-27 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, कॉनवे-टिकनर की हुई वापसी

एजेंसी

क्राइस्टचर्च । न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बुधवार को 2026-27 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार कुल 20 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। डेवोन कॉनवे और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर की वापसी हुई है। कॉनवे और टिकनर को आदित्य अशोक और मुहम्मद अब्बास की जगह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी गई है। टिकनर को घरेलू क्रिकेट और नेशनल टीम की ओर से सभी फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन के चलते सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि टिकनर और कॉनवे दोनों की वापसी देखकर अच्छा लगा। 'ब्लेयर ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत मेहनत की है और अपने गेम में काफी सुधार किया है। वह एक बेहतरीन टीम मैन हैं और पिछले कुछ महीनों में टीम के लिए अलग-अलग रोल में नजर आए हैं। यह जरूरी है कि हम अपने गेंदबाजी अटैक में उस गहराई को बनाए रखें, क्योंकि अगले 12 महीने में हमें

लाल गेंद से काफी क्रिकेट खेलनी है। इसी वजह से ब्लेयर को फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट देने से उस गहराई को बनाए रखने में मदद मिलेगी। '

उन्होंने आगे कहा, 'डेवोन पिछले कुछ समय से तीनों फॉर्मेट में टीम के नियमति सदस्य रहे हैं, यहां तक कि अनौपचारिक कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हुए भी, इसलिए उनकी काबिलियत वाले खिलाड़ी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में वापस आना बहुत अच्छा है।' न्यूजीलैंड की तरफ से 146 इंटरनेशनल मुकाबलों में कॉनवे सभी फॉर्मेट को मिलाकर 6 हजार से ज्यादा रन बना चुके हैं। कॉनवे की हालिया फॉर्म भी जबरदस्त रही है। यही वजह है कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी गई है। वहीं, टिकनर ने पिछली 8 पारियों में से 5 मुकाबलों में 4 से उससे ज्यादा विकेट निकाले हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में पहली बार पांच विकेट लेने का कारनामा पिछले महीने आयरलैंड के खिलाफ हुए एकमात्र टेस्ट के दौरान किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक रिलीज में कहा, 'टिकनर और कॉनवे के शामिल होने का मतलब है कि आदित्य अशोक और मुहम्मद अब्बास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं।' जैक फॉल्क्स और मिच हे ने पिछले साल पहली बार लिस्ट में शामिल होने और आखिरी 12 महीनों में तीनों फॉर्मेट में खेलने के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखे हैं। न्यूजीलैंड मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 2026-27: टॉम ब्लंडेल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मिशेल हे, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग।

फीफा वर्ल्ड कप: 200वां इंटरनेशनल मैच बना ऐतिहासिक, मेसी ने हैट्रिक के साथ की क्लोज के रिकॉर्ड की बराबरी

एजेंसी

नई दिल्ली । फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। अपना 200वां इंटरनेशनल मुकाबला खेलने उतरे लियोनेल मेसी का जादू इस मुकाबले में खूब चला। मेसी विश्व कप के इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अल्जीरिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मेसी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन गोल दागे। इसके साथ ही मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मेसी और क्लोज के नाम अब इस टूर्नामेंट में 16 गोल हैं। अल्जीरिया के खिलाफ मेसी शानदार लय में दिखाई दिए और उन्होंने अर्जेंटीना के लिए मैच का पहला गोल 17वें मिनट में किया। मेसी का जबरदस्त शूट गोलकीपर को छकाता हुआ निकल गया। इसके बाद दूसरे हाफ में मेसी का जलवा देखने को मिला। मैच के 60वें मिनट में मेसी ने रिबाउंड पर मिले मौके को भुनाने में कोई गलती

नहीं की और गेंद को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। मैच के 76वें मिनट में मेसी ने इस मुकाबले में गोल की हैट्रिक पूरी की। उन्होंने बॉक्स के बाहर से मिली गेंद को बाएं पैर से गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाया।

फीफा वर्ल्ड कप: अभियान की शुरुआत से पहले इंग्लिश टीम में बदलाव, लिवरामेंटो की जगह चालोबाह शामिल

एजेंसी

द्वलंदन। इंग्लैंड की टीम 17 जून की देर रात (भारतीय समय के अनुसार) क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस मैच से ठीक पहले इंग्लिश खेमे में बदलाव हुआ है। इंग्लैंड के फुल-बैक टीनो लिवरामेंटो चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। हैरी केन की कप्तानी वाली टीम ने उनकी जगह ट्रेवोह चालोबाह को शामिल करने की घोषणा की है। रविवार को 23 वर्षीय लिवरामेंटो ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए थे। इंग्लैंड फुटबॉल ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'टीनो लिवरामेंटो के चोट के कारण हटने के बाद ट्रेवोह चालोबाह को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड की 26-सदस्यीय टीम में बुलाया गया है। अब चेल्सी के इस डिफेंडर के लिए कैनसस सिटी में टीम के बेस कैंप तक यात्रा करने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि बाकी टीम बुधवार को क्रोएशिया के खिलाफ 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड टीम) के शुरुआती ग्रुप मैच के लिए डलास, टेक्सास जाएगी।' बयान में आगे कहा गया, 'फीफा के नियम हिस्सा लेने वाली टीमों को अपने शुरुआती मैच से 24 घंटे पहले तक किसी आउटफील्ड खिलाड़ी को बदलने की अनुमति देते हैं। न्यूकैसल यूनाइटेड के डिफेंडर लिवरामेंटो को रविवार दोपहर ट्रेनिंग के दौरान पिंडली में चोट लग गई थी। इसके बाद सोमवार को हुए स्कैन और मेडिकल जांच से दुर्भाग्य से पुष्टि हुई कि वह इंग्लैंड के टूर्नामेंट में आगे कोई भूमिका नहीं निभा पाएंगे। ' डिफेंस में दोनों तरफ खेलने वाले टीनो लिवरामेंटो जांघ की चोट के कारण टूर्नामेंट में पूरी तरह मैच-फिट नहीं थे। वह फ्लोरिडा में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले के दूसरे हाफ में खेले थे, लेकिन कोस्टा रिका के विरुद्ध टीम के आखिरी वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच के दौरान बेंच पर ही रहे। इंग्लैंड ने साल 1966 में अपना इकलौता फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता था। यह टीम इस साल 6 दशक के सूखे को समाप्त करने उतरेगी। इंग्लिश टीम ने साल 1990 और 2018 का सेमीफाइनल खेला था, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सकी।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड की अपडेटेड टीम:

गोलकीपर: जॉर्डन पिकफोर्ड, डीन हेंडरसन, जेम्स ट्रैफर्ड। डिफेंडर: रीस जेम्स, एजरी कोंसा, जैरेल क्वानसाह, जॉन स्टोन्स, मार्क गुएही, डैन बर्न, निको ओ'राइली, जेड स्पेंस, ट्रेवोह चालोबाह।

मिडफील्डर: डेक्लान राइस, इलियट एंडरसन, कोबी मेनू, जॉर्डन हेंडरसन, मॉर्गन रोजर्स, जूड बेलिंगहम, एबेरेची एजे।

फॉरवर्ड: हैरी केन, इवान टोनी, ओली वॉटकिंस, बुकायो साका, मार्कस रैशफोर्ड, एंथनी गॉर्डन, नोनी माडुके।

मेक्सिको करेगा एलए 28 महिला बास्केटबॉल प्री-क्वालिफायर मुकाबलों की मेजबानी

एजेंसी

मीस (स्विट्जरलैंड) । इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन (एफआईबीए) ने बताया है कि 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स के लिए महिला बास्केटबॉल प्री-क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन मेक्सिको के ग्वाडलहारा में किया जाएगा। सितंबर में बर्लिन में होने वाले 2026 एफआईबीए ??महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहने वाली आठ टीमें 17 से 23 अगस्त तक ओलंपिक प्री-क्वालिफायर में हिस्सा लेंगी। सिर्फ टूर्नामेंट की विजेता ही फरवरी 2028 में होने वाले एफआईबीए ??महिला ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करेगी। अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सेनेगल, साउथ सूडान और मेक्सिको (जो कोलंबिया की जगह लेगा) को अपने ओलंपिक सपनों को पूरा करने का एक और मौका मिलेगा। मेक्सिको को यह मौका इसलिए मिला है, क्योंकि वह महिलाओं की एफआईबीए विश्व रैंकिंग में अपने महाद्वीप की सबसे ऊंची रैंक वाली ऐसी टीम है, जिसने पहले टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। अब वह कोलंबिया की जगह प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। यह फैसला एफआईबीए के नियमों के अनुरूप लिया गया है, जिसके तहत किसी टीम के हटने की स्थिति में उसकी जगह योग्य और सर्वोच्च रैंक वाली उपलब्ध टीम को मौका दिया जाता है।

ओलंपिक क्वालिफायर में हिस्सा लेने वाली 16 टीमों में अफ्रीका की टॉप दो टीमें, अमेरिका और एशिया की टॉप चार-चार टीमें, और यूरोप की टॉप छह टीमें शामिल होंगी, जिसमें संबंधित क्षेत्र से प्री-क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का विजेता शामिल नहीं होगा। 2026 वर्ल्ड कप विजेता और मेजबान अमेरिका, जिसे एफआईबीए?? सेंट्रल बोर्ड से मंजूरी मिलनी बाकी है। 2028 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की बाकी 10 सबसे अच्छी टीमों के साथ लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में मुकाबला करेगा। प्री-क्वालिफायर का ड्रॉ शुक्रवार को एफआईबी हेडक्वार्टर में पैट्रिक बॉमन हाउस ऑफ बास्केटबॉल में होगा।

एफआईबीए विमेंस ओलंपिक प्री-क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले आठ देशों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा जाएगा। हर टीम अपने ग्रुप में दूसरे विरोधियों के खिलाफ सिंगल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी।

महिला टी-20 विश्व कप : भारत के खिलाफ मैच में धीमी ओवर गति पर पाकिस्तान टीम पर जुर्माना

एजेंसी

बर्मिंघम। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने महिला टी-20 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान निर्धारित समय में ओवर पूरे नहीं करने पर पाकिस्तान टीम पर जुर्माना लगाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप-ए मुकाबले में धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण आईसीसी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों की मैच फीस का पांच प्रतिशत काटने का फैसला लिया है। अमीरात आईसीसी अंतरराष्ट्रीय मैच रेफरी पैनल की सदस्य ट्रूडी एंडरसन ने यह दंड लगाया। समय से संबंधित सभी छूटों को ध्यान में रखने के बाद पाकिस्तान टीम को निर्धारित लक्ष्य से एक ओवर पीछे पाया गया। आईसीसी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार न्यूनतम ओवर गति नियम का उल्लंघन होने पर टीम के खिलाड़ियों पर प्रत्येक कम फेंके गए ओवर के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने गलती स्वीकार करते हुए प्रस्तावित सजा को मान लिया, जिसके बाद औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी।

इंडियन एथलेटिक्स सीरीज: किरण पहल ने जीती महिलाओं की 400 मीटर दौड़, पुरुषों में प्रदीप अव्वल

एजेंसी

सूरत। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के 12वें चरण में हरियाणा की इंटरनेशनल रनर किरण पहल ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ जीती। सूरत में आयोजित प्रतियोगिता में 25 वर्षीय किरण ने 53.49 सेकेंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। इस सीजन किरण पहल का बेस्ट 52.89 सेकेंड रहा है, जो हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के लुधियाना चरण में दर्ज किया गया था। उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था। 400 मीटर दौड़ में उनका पर्सनल बेस्ट 50.92 सेकेंड है। 48.41 सेकेंड का समय लेकर तमिलनाडु के प्रदीप एस. ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ का खिताब अपने नाम किया। हरियाणा के नवीन कुमार डागर ने लंबे समय बाद प्रतियोगिता में वापसी करते हुए पुरुषों की 3,000 मीटर स्टीपलचेज दौड़ 9:09.80 सेकेंड में जीती। दिल्ली की चारू शौकीन ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ 12.29 सेकेंड में अपने नाम की। वहीं, मध्य प्रदेश की हीरल जौहरी (12.56 सेकेंड) दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि उत्तर प्रदेश की चार्वी पुजारी (12.79 सेकेंड) ने तीसरा स्थान हासिल किया।

परिणाम:

मेंस:

400 मीटर: प्रदीप एस. (तमिलनाडु) 48.41 सेकेंड, ब्रजेश सिंह (मध्य प्रदेश) 48.70 सेकेंड, वेदांत सनस्से (महाराष्ट्र) 48.85 सेकेंड।

800 मीटर: नीलकंठ राय (आर्मी) 1:50.45, शिवा तोमर (उत्तर प्रदेश) 1:50.78, अमन कुमार (हरियाणा) 1:51.98 सेकेंड। 400 मीटर बाधा दौड़: निखिल भारद्वाज (नौसेना) 52.69 सेकेंड, सुनील मौर्य (महाराष्ट्र)

52.92 सेकेंड, रक्षित आर. (एनसीओई बेंगलुरु) 53.80 सेकेंड।

3,000 मीटर स्टीपलचेज: नवीन कुमार डागर (हरियाणा) 9:09.80 सेकेंड, आशीष पाल (ऑल इंडिया पुलिस) 9:21.28 सेकेंड, राज कुमार (उत्तर प्रदेश) 9:21.85 सेकेंड।

लंबी कूद: अविनाश कुमार (हरियाणा) 7.72 मीटर, लखवीर सिंह (पंजाब) 7.58 मीटर, भूपेंदर सिंह (रेलवे स्पोर्ट्स) 7.56 मीटर।

ट्रिपल जंप: जय शाह (महाराष्ट्र) 15.68 मीटर, विवेक गुप्ता (महाराष्ट्र) 15.44 मीटर, भुवा कैलास (गुजरात) 14.78 मीटर।

भाला फेंक: आदित्य (हरियाणा) 67.74 मीटर, सर्वेश भारत (महाराष्ट्र) 66.40 मीटर, नितेश यादव (सेना) 65.05 मीटर।

विमेंस:

100 मीटर: चारू शौकीन (दिल्ली) 12.29 सेकेंड, हीरल जौहरी (मध्य प्रदेश) 12.56 सेकेंड, चारवी पुजारी (उत्तर प्रदेश) 12.79 सेकेंड।

400 मीटर: किरण पहल (हरियाणा) 53.49 सेकेंड, आकांक्षा गावड़े (महाराष्ट्र) 58.70 सेकेंड, रमा तंवर (राजस्थान) 1:02.21 सेकेंड।

800 मीटर: अमनदीप कौर (पंजाब) 2:18.88, अंजलि (उत्तर प्रदेश) 2:19.94, अनुवा दास (पश्चिम बंगाल) 2:20.15 सेकेंड।

3,000 मीटर स्टीपलचेज: कुमारी परुरू (राजस्थान) 11:05.58 सेकेंड, सलोनी (राजस्थान) 11:12.84 सेकेंड, मोरी वंदना (गुजरात) 11:17.08 सेकेंड।

ट्रिपल जंप: अलीना टी साजी (केरल) 12.88 मीटर, अर्शदीप कौर (पंजाब) 12.67 मीटर, जेनिमोल जॉय (अखिल भारतीय पुलिस) 12.42 मीटर।

पीयूष गोयल ने फ्रांस में किया यूपीआई लॉन्च

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस शहर में मशहूर गैलरीज लाफायेट में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लॉन्च किया। इससे फ्रांस जाने वाले भारतीय यात्री जाने-पहचाने प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'भारत के वर्ल्ड-क्लास डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को फ्रांस के प्रमुख रिटेल डेस्टिनेशन में से एक में लाना यूपीआई के ग्लोबल विस्तार में एक और अहम कदम है। लाइरा कलेक्ट और एनआईपीएल की भागीदारी के साथ, यह पहल बड़े पैमाने पर भरोसेमंद, आसान और इंटरऑपरेबल डिजिटल समाधान देने की भारत की क्षमता को दिखाती है।'

उन्होंने कहा, 'यह लॉन्च भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत करता है, जो हमारी रणनीतिक

साझेदारी की बढ़ती गहराई और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।' यह डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर दोनों देशों के बीच व्यापार के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाता है। इससे यात्रियों को तुरंत सुविधा मिलती है क्योंकि उन्हें फिजिकल करेंसी एक्सचेंज, भारी मात्रा में कैश ले जाने या विदेशी मुद्रा एक्सचेंज की अनजान फीस जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता।

इससे फ्रांसीसी व्यवसायों को भी आर्थिक बढ़ावा मिलेगा, जिन्हें बड़ी संख्या में तकनीक-प्रेमी भारतीय पर्यटकों तक तुरंत पहुंच मिलेगी, जिससे ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़ेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थानीय व्यापारियों को भी बेहतर कैश मैनेजमेंट, डिजिटल कैश संभालने से जुड़ी कम लागत और सुरक्षित, रियल-टाइम ट्रांजैक्शन सेटलमेंट का लाभ मिलेगा।

3 जून को कंबोडिया के बाद फ्रांस दूसरा देश है, जहां यूपीआई लॉन्च किया गया है। यह अहम सहयोग नोम पेन्ह में एक औपचारिक समारोह के बाद शुरू हुआ, जिसमें कंबोडिया के नेशनल बैंक की गवर्नर चिया सेरे और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हुए।

बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के साथ ही दोनों देशों के बीच बाकोंग के केएचक?यूआर (कंबोडिया का नेशनल क?यूआर कोड) के जरिए क्रॉस-बॉर्डर क?यूआर पेमेंट लिंक स्थापित करने का पहला चरण पूरा हो गया।

पहला चरण लाखों भारतीय यात्रियों को 45 लाख से ज्यादा कंबोडियाई व्यापारियों के यहां आसानी से क्यूआर पेमेंट करने की सुविधा देता है और इसके बाद टू-वे (दोनों तरफ से) कॉरिडोर शुरू होगा।

हालांकि पहले चरण में फ्रांस आने वाले भारतीय यात्रियों को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन इस साझेदारी को बड़े पैमाने पर विस्तार देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अकासा एयर ने नवी मुंबई से नोएडा के बीच शुरू की उड़ान सेवा

एजेंसी
मुंबई। अकासा एयर ने मुंबई और नोएडा के बीच अपनी उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। घरेलू एयरलाइन कंपनी ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मंगलवार सुबह क्यूपी-2017 विमान को रवाना करते हुए नव निर्मित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सेवाएं शुरू कर दी, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र और दिल्ली-एनसीआर के बीच अकासा एयर की सीधा हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एनएमआईएएल) के प्रवक्ता के अनुसार अकासा एयर की पहली उड़ान सुबह साढ़े सात बजे नवी मुंबई से रवाना हुई और यह दोपहर साढ़े 12 बजे वापस नवी मुंबई हवाई अड्डे पहुंची। एयरलाइन इस मार्ग पर सप्ताह में सात उड़ानों का संचालन करेगी। अकासा एयर ने एक्स पोस्ट में बताया कि आज हमारी यात्रा में एक अहम पड़ाव है, क्योंकि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हमारी पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी, जिससे एनसीआर में हमारी मौजूदगी और मजबूत हुई है। एयरलाइन ने कहा कि बेंगलुरु और नवी मुंबई से नोएडा के लिए रोज़ाना नॉन-स्टॉप उड़ानों के साथ हम भारत के सबसे अहम एविएशन मार्केट में कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जिससे यात्रा और भी आसान और सुलभ हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि इसके अलावा हम एयरपोर्ट परिसर में एक अत्याधुनिक एमआरओ सुविधा भी चलाएंगे, जो ऑपरेशनल दक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मज़बूत करेगा।

जीआईसी का बिक्री पेशकश पहले दिन 3.72 गुना हुआ सब्सक्राइब

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) में पांच फीसदी तक की हिस्सेदारी बिक्री पेशकश (ओएफएस) 3.72 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ। इसमें संस्थागत निवेशकों ने 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की बोली लगाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के आंकड़ों के अनुसार गैर-खुदरा निवेशकों ने 11.73 करोड़ जीआईसी शेयरों के लिए आज बोली लगाई, जो 3.16 करोड़ शेयर के निर्गम का 3.72 गुना है। इसके 352.92 रुपये के सांकेतिक मूल्य पर इन बोलियों का कुल मूल्य लगभग 4 हजार करोड़ रुपये है। वहीं, खुदरा निवेशक बिक्री पेशकश (ओएफएस) के लिए बुधवार को बोली लगा सकेंगे। जीआईसी में सरकार दो दिवसीय बिक्री पेशकश के तहत 352 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर दो फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है। इसमें तीन फीसदी का ग्रीन-शू विकल्प भी शामिल है। इस तरह कुल हिस्सेदारी बिक्री पांच फीसदी हो जाएगी, जो 8.77 करोड़ से अधिक शेयर के बराबर है। ये न्यूनतम मूल्य सोमवार के बंद भाव से 9.36 फीसदी कम था, जबकि कंपनी का शेयर बीएसई पर 7.65 फीसदी टूटकर 358.65 रुपये पर बंद हुआ है।

सरकार इस बिक्री से लगभग 3 हजार करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही है। इसमें ग्रीन-शू विकल्प का इस्तेमाल किए जाने की भी संभावना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 80 हजार करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बिक्री और परिसंपत्ति मौद्रीकरण का है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर अब तक 13,389 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ, निवेशकों ने कमाये 2.71 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते तथा कच्चे तेल की कीमत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई गिरावट से उत्साहित शेयर बाजार आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत भी मजबूती के साथ हुई थी। दिन के पहले सत्र के दौरान बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहा, लेकिन दूसरे सत्र में खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया। लिवाली के सपोर्ट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक अच्छी बढ़त हासिल करने में सफल रहे। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.71 प्रतिशत और निफ्टी 0.57 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एनर्जी और मीडिया सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। इसी तरह एफएमसीजी, रियल्टी, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। दूसरी ओर, मेटल, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयरों में आज लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज खरीदारी होती रही, जिसके कारण निफ्टी का मिडकैप इंडेक्स 0.41 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया।

भारतीय बाजार में जल्द लान्च होगी एवोर की इलेक्ट्रिक बाइक

एजेंसी
नई दिल्ली। पेट्रोल महंगा होने से भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मांग लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर Samarth E-Mobility Private Ltd जिसने हाल ही में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में एंट्री ली है। कंपनी की एक नई इलेक्ट्रिक बाइक को पहली बार सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह कंपनी पूरी तरह से भारत में बने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इकोसिस्टम पर काम कर रही है। इसके तहत कंपनी अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी पार्ट्स तैयार कर रही है।

ये मिलेंगे फीचर्स:
150cc से 200cc की बाइक की तरह Avore की नई इलेक्ट्रिक बाइक में नई प्रीमियम पार्ट्स दिए गए हैं। इस बाइक में अलॉय व्हील्स, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स, चारों चरफ LED लाइटिंग, मस्कुलर लुक और भारी-भरकम बॉडी वर्क देखा जा सकता है जो बैटरी पैक तक

जाता है। इसके अलावा इसमें, स्प्लिट सीट्स, पीछे दो हिस्सों में बंटा हुआ ग्रैब रेल और TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी चीजें दिख रही हैं।

आराम और कनेक्टिविटी:
इसमें स्ट्रीट -स्टाइल हैंडल बार, पीछे की तरफ सेट किए गए फुटपेग्स और बैठने का नेचुरल तरीका दिया गया है जिससे राइडर्स आसानी से और आराम में सफर कर सकेंगे। इसके इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड तकनीक मिल सकती है जो नोटिफिकेशन, म्यूजिक कंट्रोल और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी सुविधाएं दिखा सकती हैं।

ये होगी इसकी खासियत:
इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को 10.5 किलोवाट की क्षमता वाली मोटर के साथ लॉन्च किया जाएगा। साथ ही, इसमें 5kWh की क्षमता की बैटरी पैक दी जाएगी जो IP67 रेटिंग के साथ आएगी। इस बाइक में AI के साथ ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। इसकी मदद से नेविगेशन के साथ-साथ कई अन्य जानकारियां भी देखी जा सकेंगी।

जल्द हो सकती है लॉन्च:
हाल ही में टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल से पता चलता है कि ,1शहद्ध की यह नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पूरी तरह से बनकर तैयाक लग रही है। यह बाइक जल्द ही भारतीय इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्कट में एंट्री कर सकती है।

अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीद से 80 डॉलर से नीचे फिसला ब्रेंट क्रूड, रुपए को भी मिला सपोर्ट

एजेंसी
नई दिल्ली । वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को करीब 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशक और कारोबारी इस संभावना का आकलन कर रहे हैं कि ईरान से जुड़ा संघर्ष समाप्त हो सकता है और होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से खुल सकता है। अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.72 प्रतिशत गिरकर 78.39 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड लगभग 1 प्रतिशत फिसलकर 75.35 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के अंतरिम समझौते से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा, जबकि एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ईरान को तेल बेचने की अनुमति दी जाएगी। इस सप्ताह हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत अप्रैल में घोषित युद्धविराम को 60 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है, ताकि दोनों पक्ष स्थायी शांति समझौते पर बातचीत कर

सकें। समझौते के अनुसार अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर लगाया गया अपना प्रतिबंध हटाएगा, जबकि तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों और अन्य समुद्री यातायात को गुजरने की अनुमति देगा। अमेरिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को हमले शुरू किए जाने के बाद से ईरान ने इस मार्ग को प्रभावी रूप से बाधित कर रखा था। इस बीच भारतीय रुपया भी मजबूत हुआ। बुधवार को घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे की बढ़त के साथ 94.29 पर कारोबार कर रही थी, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 94.56 पर बंद हुई थी।

विशेषज्ञों के अनुसार एक और सकारात्मक संकेत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निकासी में कमी आना है। उनका मानना है कि यह रुझान आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि रुपया लगातार मजबूत हो रहा है और इसमें आगे और मजबूती आने की संभावना है। विशेषज्ञों ने कहा, 'ब्रेंट क्रूड में तेज गिरावट के बाद इसका भाव 79 डॉलर के आसपास आ गया है। साथ ही एफसीएनआर (बी) डिपॉजिट योजना के जरिए भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी प्रवाह की उम्मीद है। इससे रुपए में और मजबूती आ सकती है, जो एफआईआई को बिकवाली से और हतोत्साहित करेगी। '

विश्व के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स की सूची में अडाणी समूह के दो हवाई अड्डे शामिल

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की एयरपोर्ट संचालक कंपनी अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) को प्रतिष्ठित 'प्रिक्स वर्साय' आर्किटेक्चर और डिजाइन अवॉर्ड्स में ग्लोबल पहचान मिली है। अडाणी समूह की ओर से संचालित देश के दो हवाई अड्डों को विश्व के सबसे खूबसूरत हवाईअड्डे की सूची में शामिल किया गया है। कंपनी के मुताबिक अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) और गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एलजीबीआईए) के टर्मिनल 2 को 'प्रिक्स वर्साय' की 'दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स' की 2026 की सूची में शामिल किया गया है। एएएचएल ने कहा कि यह सम्मान अगली पीढ़ी के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आकार देने में एएएचएल के बढ़ते प्रभाव को उजागर करता है, जिसमें अत्याधुनिक डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी और यात्रियों पर केंद्रित इनोवेशन पर खास ध्यान दिया गया है।

केंद्र सरकार ने डीजल, एटीएफ निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, नई दरें लागू

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विंडफॉल टैक्स) बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर मौजूदा कर को बरकरार रखा है। शुल्क में यह बढ़ोतरी 16 जून से लागू हो गई है। वित्त मंत्रालय ने देर रात एक अधिसूचना में बताया कि 16 जून से डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 9.50 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली शुल्क दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह 1.50 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। अधिसूचना में कहा गया है कि शुल्क में बढ़ोतरी 16 जून से लागू होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भारत और मोनाको के संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे : पीयूष गोयल

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि उन्होंने मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट II से मुलाकात की और स्थिरता, ब्लू इकोनॉमी, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में भारत-मोनाको साझेदारी के विस्तार पर चर्चा की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उन्होंने नीस में आयोजित प्रमुख 'भारत इनोवेट्स 2026' कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी, जिसने भारत के जीवंत प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम को प्रदर्शित किया तथा वैश्विक सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोयल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'मुझे विश्वास है कि भारत-मोनाको संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। 'इससे पहले, पीयूष गोयल ने नीस में आयोजित 'भारत इनोवेट्स 2026' के समापन समारोह को संबोधित किया और पिछले तीन दिनों में प्राप्त उपलब्धियों पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियां भारत-फ्रांस नवाचार साझेदारी की

अपार संभावनाओं को दर्शाती हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के प्रेरणादायक नेतृत्व तथा 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026' के तहत उनकी साझा दृष्टि ने उस मजबूत नींव का निर्माण किया, जो आज एक वास्तविक परिवर्तनकारी मंच के रूप में उभरकर सामने आई है।केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में कहा, 'मैंने उद्योग जगत के नेताओं, सीईओ, निवेशकों और नवोन्मेषकों को बड़े पैमाने पर नवाचार से संचालित एक उज्ज्वल और सतत भविष्य के निर्माण के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का निमंत्रण दिया। ' केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के ग्रास शहर स्थित प्रतिष्ठित फ्रैगोनार्ड फैक्ट्री का भी दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्हें उस ऐतिहासिक विरासत की प्रेरक झलक देखने को मिली, जिसने कई पीढ़ियों से वैश्विक इत्र और सुगंध उद्योग को आकार दिया है। उन्होंने लक्जरी विनिर्माण, डिजाइन और उच्च मूल्य व्यापार के क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग को और गहरा करने की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की। पीयूष गोयल ने कहा, 'फ्रांस की विशेषज्ञता को भारत की समृद्ध विरासत, गहन पारंपरिक ज्ञान और कुशल कार्यबल के साथ जोड़कर हम नवाचार के नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं और प्रीमियम सुगंध तथा लक्जरी क्षेत्रों में भारत को एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। ' इसके अलावा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नीस शहर में स्थित प्रतिष्ठित गैलरीज लफाएटे नाइस मसीना में भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का शुभारंभ भी किया।

स्टॉक मार्केट में उत्कल स्पेशलिटी की निराशाजनक शुरुआत, फ्लैट लिस्टिंग के बाद लगा लोअर सर्किट

एजेंसी
नई दिल्ली। ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से पेपर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी उत्कल स्पेशलिटी के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 66 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग बिना किसी उतार चढ़ाव के 66 रुपये के स्तर पर ही हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण ये शेयर टूट 62.70 रुपये के लोअर सर्किट लेवल तक गिर गया। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को प्रति शेयर 3.30 रुपये यानी पांच प्रतिशत का नुकसान हो गया उत्कल स्पेशलिटी का 34.54 करोड़ रुपये का आईपीओ 10 से 12 जून के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.60 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.12 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में सिर्फ 0.89 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 2.10 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 52.34 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

भू-राजनीतिक तनाव कम होने से सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट, घटी सुरक्षित निवेश की मांग

एजेंसी
मुंबई । भू-राजनीतिक तनाव में कमी आने से सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) की मांग कमजोर हुई, जिसके चलते बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशक और कारोबारी इस सप्ताह के अंत में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले समझौते की अंतिम पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में 0.51 प्रतिशत यानी 790 रुपए की गिरावट आई और दिन के कारोबार में यह 1,52,301 रुपए के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक पीली धातु 590 रुपए या 0.39 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,52,501 रुपए प्रति 10 ग्राम पर

कारोबार कर रही थी। इससे पहले यह 1,53,179 रुपए के दिन के उच्चतम स्तर तक पहुंची थी, जो पिछले बंद भाव 1,53,091 रुपए की तुलना में 88 रुपए या 0.05 प्रतिशत अधिक था। वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी का 195 रुपए या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,49,910 रुपए पर कारोबार करती नजर आई। सफेद धातु ने दिन के कारोबार के दौरान 1,328 रुपए या 0.53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करते हुए 2,48,777 रुपए का निम्नतम स्तर छुआ। वहीं इसका दिन का उच्च स्तर 2,51,498 रुपए रहा, जो पिछले बंद भाव की तुलना में 1,393 रुपए या 0.55 प्रतिशत अधिक था। दिन की शुरुआत में कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1,52,800 रुपए और चांदी 2,50,557 रुपए पर खुली थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स चांदी 0.55 प्रतिशत की बढ़त के साथ 70.40 डॉलर पर कारोबार कर रही थी, जबकि कॉमेक्स सोना 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,348.70 डॉलर प्रति औंस पर था। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, एमसीएक्स सोना फिलहाल 1,52,000 से 1,52,500 रुपए के महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है और बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। यदि कीमतें लगातार 1,53,500 से 1,54,000 रुपए के दायरे से ऊपर बनी रहती हैं तो बाजार में स्थिरता आ सकती है और सोना 1,55,000 से 1,55,500 रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि, यदि कीमत 1,52,000 रुपए से नीचे जाती है तो नई बिकवाली शुरू हो सकती है, जिससे सोना पहले 1,51,000 रुपए और फिर 1,50,000 रुपए तक फिसल सकता है।

टाटा सिएरा ईवी 30 जून को होगी लान्च, ट्रिपल-स्क्रीन के साथ मिल सकते हैं कई फीचर्स

एजेंसी
नई दिल्ली। टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में 30 जून को सिएरा ईवी को लान्च करने वाला है। इसके साथ ही कंपनी अपने इस आइकॉनिक नाम को पूरी तरप से इलेक्ट्रिक रूप से वापस ला रही है। इस मॉडल को सबसे पहले ऑटो एक्सपो2020 में एक कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। लेकिन अब TATA Sierra EV इस महीने के आखिर में लॉन्च होने वाली है।

डिजाइन और एक्सटीरियरः
उम्मीद है कि Sierra EV में कई ऐसे डिजाइन बदलाव देखने को मिलेंगे जो इसे ICE मॉडल से अलग बनाएंगे। इसके बाहरी हिस्से में बंद फ्रंट ग्रिल, एक बदला हुआ बंपर और खास तौर पर EV के लिए दिए गए डिजाइन टच शामिल हो सकते हैं। हालांकि, टीजर में दिखे दोनों मॉडल्स में एक जैसे अलॉय व्हील्स नजर आ रहे हैं लेकिन TATA Motors इल इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए खास व्हील डिजाइन पेश कर सकती है।

इंटीरियर और संभावित फीचर्स:
Sierra EV का केबिन काफी हद तक इसके पेट्रोल मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है जिसमें आराम और तकनीक का पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसके महंगे वेरिएंट्स में ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट मिल सकता है। इसमें 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और आगे बैठने वाली पैसेंजर के लिए अलग से 12.3 इंच की स्क्रीन शामिल हो सकता है। इसके लोअर वेरिएंट्स में डुअल-स्क्रीन वाला सेटअप और साथ में एक हेड-अप डिस्प्ले मिल सकता है। Sierra EV टाटा के acti.ev+ प्लैटफॉर्म पर आधारित होगी जिस पर Harrier EV भी बनी है।

उम्मीद है कि इसमें बैटरी पैक के विकल्प भी एक जैसे होंगे जिसमें 65kWh और 75kWh के विकल्प दिए जा सकते हैं। TATA ने पहले ही साफ कर दिया है कि Seirra EV रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों वर्जन में आएगी।

केंद्र ने भारत और खाड़ी देशों के बीच गहरे समुद्र में एनर्जी पाइपलाइन से जुड़ी खबरों को किया खारिज

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को ख़ारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि वह गुजरात को ओमान और अन्य खाड़ी देशों से जोड़ने वाली गहरे समुद्र में ऊर्जा पाइपलाइन पर काम कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि उसने ऐसी कई मीडिया रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें कहा गया है कि भारत सरकार गहरे समुद्र में ऊर्जा पाइपलाइन बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, जिसे कभी-कभी 'मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन' (एमईआईडीपी) कहा जाता है और यह पाइपलाइन गुजरात को ओमान और अन्य खाड़ी देशों से जोड़ेगी। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि इस समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस प्रोजेक्ट को लेकर ओमान या किसी अन्य खाड़ी देश के साथ मंत्रालय के किसी भी स्तर पर कोई सक्रिय चर्चा या बातचीत नहीं हो रही है। मंत्रालय ने बयान में कहा, कि यह स्पष्टीकरण इस मामले से जुड़ी सभी अटकलों को खत्म करने के लिए जारी किया गया है। पेटोलियम मंत्रालय ने कहा कि एलएनजी जहाज दिशा सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुका है। यह जहाज 62,370 टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) लेकर आ रहा है। ये जहाज गुजरात राज्य के भरूच जिले में खंभात की खाड़ी के तट पर स्थित प्रमुख औद्योगिक और बंदरगाह शहर दहेज के लिए एलएनजी लेकर जा रहा है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला लायोटेक इंडस्ट्रीज का आईपीओ, 24 जून को हो सकती है लिस्टिंग

एजेंसी
नई दिल्ली । हार्डवेयर स्ट्रक्चजर और एसेसरीज का निर्माण करने वाली कंपनी लायोटेक इंडस्ट्रीज का 36.02 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 19 फरवरी तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 22 जून को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 23 जून को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 24 जून को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 321 रुपये प्रति शेयर का मूल्य तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 400 शेयर का है। लायोटेक के इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 800 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,56,800 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 11.22 लाख शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें 27 करोड़ रुपये के 8.42 लाख नए शेयर और 7 करोड़ रुपये के 2.22 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 47.42 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 47.41 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.17 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रखा गया है। इस इश्यू के लिए वेल्थ माइन नेटवर्क्स प्रा.लि. को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं ऐक्यम कैपिटल प्रा.लि. कंपनी का मार्केट मेकर है। लायोटेक इंडस्ट्रीज की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 35 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 2.93 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 4.16 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी को 5.49 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हो चुका था।

इस दौरान कंपनी की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में इसे 8.50 करोड़ का कुल राजस्व प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 27.87 करोड़ और वित्त वर्ष 2024-25 में उछल कर 40.69 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी को 51.79 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका था।

इस अवधि में कंपनी के कर्ज में भी लगातार वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी पर 1.38 करोड़ रुपये का कर्ज था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 3.55 करोड़ रुपये और 2024-25 में 4.22 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी पर लदे कर्ज का बोझ बढ़ कर 4.81 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया था। इस अवधि में कंपनी के रिजर्व और सरप्लस में भी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2022-23 में ये 0.36 लाख रुपये के स्तर पर था, जो 2023-24 में बढ़ कर 3.28 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का रिजर्व और सरप्लस 7.45 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक ये 12.93 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह ईबीआईटीडीए (अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट, टैक्सेज, डिप्रेशिएशंस एंड एमॉर्टाइजेशन) 2022-23 में 87 लाख रुपये के स्तर पर था, जो 2023-24 में बढ़ कर 4.45 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह 2024-25 में कंपनी का ईबीआईटीडीए 6.56 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। वहीं पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक ये 8.39 करोड़ रुपये के स्तर पर था।

जी-7 शिखर सम्मेलन : उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग की स्वतंत्रता पर दिया जोर

एजेंसी

एवियन। फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने मध्य पूर्व की स्थिति, होर्मुज स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता और वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों की आवश्यकता पर जोर दिया। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, ''फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में मध्य पूर्व पर क्षेत्रीय साझेदारों के साथ हुई बैठक में सबसे पहले, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि होर्मुज स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता पूरी तरह बहाल हो और उस पर किसी तरह की पाबंदी न हो।'' साथ ही उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में हुई हाल की घटनाओं ने कुछ कमजोरियों को उजागर किया है, जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें मिलकर वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों और नए कॉरिडोर पर काम करना चाहिए, जैसे कि आईएमईसी। बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए हम इन कमजोरियों को अवसरों में बदल सकते हैं। एक स्थिर और शांतिपूर्ण मध्य पूर्व के लिए लेबनान का स्थिर और शांतिपूर्ण होना भी जरूरी है।जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस पर युद्ध समाप्त करके समझौता करने का दबाव बनाया। ट्रंप ने कहा कि वहां जो हो रहा है, वह पागलपन है। हमारी एक मीटिंग हुई थी और मैंने रविवार को राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। वे बस लड़ते जा रहे हैं और सैनिक खोते जा रहे हैं।

ईरान-अमेरिका शांति समझौते की दिशा में बड़ा कदम, शुक्रवार से अंतिम समझौते पर शुरू होगी वार्ता : ईरानी विदेश मंत्री

एजेंसी

तेहरान । ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव और संघर्ष के बाद अब शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच अंतिम समझौते पर बातचीत का नया दौर शुक्रवार से शुरू होगा। इससे पहले दोनों देशों ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अंतिम रूप दिया है, जिस पर शुक्रवार को आधिकारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, तेहरान में विदेशी राजनयिकों के साथ बैठक के दौरान अराघची ने इस समझौते की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को दो चरणों में बांटा गया है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हुए हमलों के कारण कई जटिलताएं पैदा हो गई थीं। विदेश मंत्री के अनुसार, पहले चरण में युद्ध समाप्त करने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी, ईरान की जमी हुई संपत्तियों और युद्ध से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है। वहीं दूसरे चरण में अगले 60 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। अराघची ने कहा कि इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू युद्ध समाप्ति की घोषणा है। उन्होंने बताया कि समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सोमवार सुबह युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी गई थी, जबकि समझौता ज्ञापन आधिकारिक रूप से शुक्रवार से लागू होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस समझौते में लेबनान की स्थिति को भी शामिल किया गया है। अराघची के मुताबिक लेबनान में युद्ध का अंत और वहां से इजरायली सेना की वापसी इस शांति प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। जब तक कब्जे वाले लेबनानी क्षेत्रों से इजरायली सैनिक नहीं हटते, तब तक युद्ध की समाप्ति को पूर्ण नहीं माना जा सकता।ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब से लेबनान पर इजरायल का कोई भी सैन्य हमला या वहां कब्जा बनाए रखना शांति समझौते का उल्लंघन माना जाएगा।

बता दें कि अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान ने सोमवार को कई सप्ताह की वार्ताओं के बाद युद्ध समाप्ति संबंधी समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी। इस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने तेहरान समेत कई ईरानी शहरों पर संयुक्त हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे।

भारत-श्रीलंका रक्षा सहयोग और मजबूत, 55 लाख डॉलर की सैन्य सहायता सौंपी

एजेंसी

कोलंबो। भारत के श्रीलंका में उच्चायुक्त ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) मिशन में तैनाती के लिए श्रीलंकाई सेना को सैन्य उपकरण सौंपे। ये उपकरण 55 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि के तहत दिए गए हैं। भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'पर लिखा, 'भारत-श्रीलंका के रक्षा संबंधों को मजबूत करने और काम करने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम। मुझे खुशी है कि भारतीय सेना की ओर से श्रीलंकाई सेना को यूएन मिशन के लिए सैन्य सामान सौंपा गया, जो 55 लाख डॉलर की सहायता के तहत दिया गया है।' उन्होंने कहा, 'श्रीलंका के अनुरोध पर भारत ने तुरंत इन उपकरणों की व्यवस्था की। यह दोनों देशों के रक्षा संबंधों में भरोसे और विश्वास को दिखाता है।'

इससे पहले अप्रैल में भारत ने श्रीलंका कोस्ट गार्ड को दो पर्सनल वॉटरक्राफ्ट (पीडब्ल्यूसी) और सुरक्षा उपकरण दिए थे।

कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने 'एक्स' पर बताया कि भारत श्रीलंका कोस्ट गार्ड की समुद्र के किनारे खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाने में मदद कर रहा है। यह सामान भारतीय उच्चायोग के रक्षा सलाहकार ने मिरिसा स्थित श्रीलंका कोस्ट गार्ड मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशंस निदेशक को सौंपा। मानवीय सहायता के तहत भारत ने 24 अप्रैल को अपनी 'आरोग्य मैत्री' पहल के तहत श्रीलंका को दो बीएचआईएसएम (भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री) क्यूब भी दिए। ये आधुनिक पोर्टेबल मेडिकल यूनिट हैं, जो 200 तक आपातकालीन मामलों को संभाल सकती हैं।

इमरान खान को पांचवीं बार इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल, बहन अलीमा ने उठाए सवाल

इस्लामाबाद । पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान महीनों से आंखों की तकलीफ से जूझ रहे हैं। सोमवार को जेल प्रशासन इलाज के लिए पांचवीं बार उन्हें अस्पताल ले गया। अब उनके परिवार ने इस मामले को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि सरकार की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी पर उन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 15 जून की सुबह उन्हें जानकारी मिली कि इमरान खान को एक बार फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (पीआईएमएस) ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल की ओर से पहले भी इमरान खान की स्थिति को लेकर 'संदिग्ध दावे' किए गए हैं, जिनमें यह कहा गया था कि उनकी 90 प्रतिशत दृष्टि ठीक हो चुकी है, जबकि इमरान खान ने स्वयं इन दावों को खारिज किया था। अलीमा खान ने सवाल उठाया कि आखिर इमरान खान को पांचवीं बार इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है और मांग की कि उनका इलाज स्वतंत्र और योग्य विशेषज्ञों से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद में कराया जाए।

इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने हिंसा के बीच 10 प्रांतों और 3 नगरपालिकाओं में आपातकाल की घोषणा

एजेंसी

क्विटो। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने आपराधिक हिंसा के कारण फैली गंभीर आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए 10 प्रांतों और तीन नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की नई घोषणा की है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आदेश के तहत गुआयास, मनाबी, सांता एलेना, लॉस रियोस, एल ओरो और एस्मेराल्डास जैसे तटीय प्रांतों में घरों की तलाशी तथा पत्राचार की गोपनीयता से संबंधित कानूनी सुरक्षा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। यह नियम पिचिंचा (उत्तर-मध्य प्रांत, जिसमें राजधानी क्विटो शामिल है), सैंटो डोमिंगो डे लॉस त्साचिलास, उत्तरी अमेज़न प्रांत सुकुम्बियोस और दक्षिणी प्रांत अजुआई पर भी लागू होता है। इस आदेश में कोटोपैक्सी प्रांत की ला माना, बोलिवर प्रांत की लास नेव्स और कैनार प्रांत की ला ट्रोनकल नगरपालिकाएं भी शामिल हैं।

राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा बलों को तुरंत तलाशी लेने की इजाजत है, जब ऐसे संकेत हों कि संगठित हथियारबंद समूहों या आपराधिक संगठनों के सदस्य किसी प्रॉपर्टी के अंदर छिपे हैं, या जब हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक या प्रतिबंधित चीजों के होने का शक हो। यह आदेश अधिकारियों को खतरों को रोकने या बेअसर करने के लिए जरूरी जानकारी की पहचान करने, उसका विश्लेषण करने और उसे इकट्ठा करने की इजाजत देता है। यह सुरक्षा अभियानों को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी गैर-कानूनी सामान और सेवाओं को कुछ समय के लिए ज़ब्त करने का अधिकार भी देता है।

आदेश के अनुसार, इक्वाडोर में हाल ही में संगठित हथियारबंद समूहों और आपराधिक संगठनों से जुड़ी हिंसक घटनाओं, हथियारबंद हमलों और आपराधिक गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है।

आदेश में कहा गया कि हत्या, जबरन वसूली, अपहरण, लूटपाट और ड्रग्स की तस्करी से सामाजिक अशांति बनी हुई है और सामान्य आर्थिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं। लोगों के मन से डर कम करने के लिए विशेष उपायों के ज़रिए सशस्त्र बलों का दखल ज़रूरी है।

भारत ने यूएन चार्टर के प्रति दोहराया समर्थन, पी. हरिश बोले- यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए 'उम्मीद'

एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) चार्टर भारतीयों के लिए उम्मीद का प्रतीक है। उन्होंने यूएन चार्टर की प्रस्तावना पर प्रतीकात्मक रूप से हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर 1945 में हुए उस ऐतिहासिक दस्तावेज की स्मृति में किए गए, जिसने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों के लिए यूएन चार्टर का महत्व एक शब्द में 'उम्मीद' है। 26 जून को मनाए जाने वाले यूएन चार्टर दिवस की तैयारी के तहत किए गए इन हस्ताक्षरों का मकसद चार्टर के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को फिर से जताना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेयरबॉक ने प्रतीकात्मक हस्ताक्षर का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि यह चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की नई अभिव्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधिमंडल के नेता ए. रामास्वामी मुदलियार ने 25 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में भारत की ओर से मूल चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। भारत संयुक्त राष्ट्र के 50 संस्थापक सदस्यों में से एक था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भागीदारी ने आजादी से पहले ही एक संस्थापक सदस्य के तौर पर उसकी भूमिका को दर्शाया, जो बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ था। बेयरबॉक के कार्यालय से इस साल के आयोजन के बारे में जारी एक नोट में कहा गया कि इस साल चार्टर के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कई तरह के दबावों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। नोट में कहा गया, 'चार्टर पर हस्ताक्षर के 81 साल बाद हम एक चौराहे पर खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र न सिर्फ राजनीतिक और वित्तीय दबाव में है, बल्कि उस पर हमले भी हो रहे हैं।'

मॉस्को क्षेत्र की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने किया हमला, ट्रंप बोले-रूस को अब समझौता कर लेना चाहिए

मास्को। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से मॉस्को क्षेत्र को निशाना बनाने का दावा किया। जेलेंस्की ने कहा ककि यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र में करीब 500 किलोमीटर दूर स्थित एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया। यह हमला रूस पर दबाव बढ़ाने और युद्ध समाप्त करने की रणनीति का हिस्सा है। यूक्रेन का ये हमला रूस के एक दिन पहले किए गए हमलों के जवाब किया गया। रूस ने रविवार की रात 70 मिसाइलों और 611 ड्रोन की मदद से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले क?िए। इन हमलों में 60 से अधिक मिसाइलें तो राजधानी कीव में ही दागी गईं। इन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कीव में 35 लोग घायल हुए हैं। पूरे देश में 53 लोग घायल बताए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया, ''इस बार मॉस्को ने भी यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमताओं का असर देखा। लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित उसकी एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया।'' जेलेंस्की ने कहा, ''मैं यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, मानवरहित सिस्टम बलों, विशेष अभियान बलों, रक्षा खुफिया विभाग और मिसाइल बलों के जवानों का उनके प्रभावी काम के लिए धन्यवाद करता हूं।''

स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता के लिए ईरानी टीम का नेतृत्व करेंगे स्पीकर गालिबाफ

तेहरान । स्विट्जरलैंड में यूएस-ईरान शांति वार्ता आगामी 19 जून को होनी तय की गई है। ईरानी टीम का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ करेंगे तो वहीं अमेरिका का मोर्चा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस संभालेंगे। दोनों पक्षों के बीच ई-हस्ताक्षर की पुष्टि की गई। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत शुक्रवार को जिनेवा में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के बाद शुरू होगी। समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार, उन्होंने बताया कि ईरान की टीम का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ करेंगे, जबकि अमेरिकी पक्ष की ओर से वार्ताकारों का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे।

बैंकॉक में भारत-थाईलैंड डिफेंस डायलॉग, रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर किया मंथन

एजेंसी

बैंकॉक । भारत और थाईलैंड ने बैंकॉक में 10वां डिफेंस डायलॉग (रक्षा वार्ता) आयोजित किया गया, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े पारस्परिक हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। आयोजित इस वार्ता की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्यजीत मोहंती और थाईलैंड के रक्षा उप-स्थायी सचिव नुट्टापोल डिएवानिच ने की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर अपने-अपने दृष्टिकोण साझा किए।

दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को और मजबूत करने के महत्व की पुनः पुष्टि की।

प्रतिनिधिमंडलों ने पिछली वार्ता के बाद से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की।

चर्चा में सैन्य-सेना संपर्क, क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग एक्सचेंज, समुद्री सहयोग तथा अन्य पारस्परिक हितों के क्षेत्रों को शामिल किया गया।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, 'वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच जारी रक्षा उद्योग सहयोग की भी समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने रक्षा विनिर्माण, अनुसंधान, नवाचार और क्षमता विकास में सहयोग को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की, ताकि दोनों देशों के रक्षा तंत्रों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारियों को बढ़ावा दिया जा सके। ' मंत्रालय ने आगे कहा, 'प्रतिनिधिमंडलों ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय रक्षा ढांचों, विशेष रूप से आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के तहत सहयोग पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने संवाद और सहयोग के माध्यम से व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने तथा साझा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ' बैठक का समापन भविष्य की सहभागिताओं और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की रूपरेखा पर चर्चा के साथ हुआ।भारत और थाईलैंड ने वर्ष 2025 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया था। रक्षा वार्ता के बाद, बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा, 'दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी तथा विभिन्न क्षेत्रीय मंचों के तहत, विशेषकर नए और उभरते क्षेत्रों में, सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। भारत-थाईलैंड समुद्री पड़ोसी है।

खैबर पख्तूनख्वा में शैक्षणिक संस्थानों पर आतंकी हमलों में बढ़ोतरी, इस साल 11 घटनाओं में 13 की मौत

एजेंसी

इस्लामाबाद। इस साल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शैक्षणिक संस्थानों पर हमले की 11 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें 13 लोगों की मौत हुई है। यह जानकारी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल (एसएटीपी) के 14 जून तक के आंशिक आंकड़ों के हवाले से दी गई एक रिपोर्ट में सामने आई है। 'यूरेशिया रिव्यू' की एक रिपोर्ट में बताया गया क? 2025 में इसी अवधि के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में किसी शैक्षणिक संस्थान पर हमले की सिर्फ एक घटना दर्ज हुई थी, जिसमें तीन बच्चे घायल हुए थे। इससे पता चलता है कि वहां स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाकर की जाने वाली आतंकी हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। 2025 के पूरे साल खैबर पख्तूनख्वा में शैक्षणिक संस्थानों पर हमले की कुल 11 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें तीन लोग घायल हुए थे। इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के रिसर्च एसोसिएट तुषार रंजन मोहंती ने 'यूरेशिया रिव्यू' में लिखा, '2006 से अब तक शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाकर कम से कम 557 हमले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 321 लोगों की मौत हुई और 208 लोग घायल हुए हैं। हालांकि, खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में मीडिया की पहुंच सीमित है और सरकारी एजेंसियों से भी जानकारी लगातार नहीं मिलती, इसलिए असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। ' रिपोर्ट के अनुसार, किसी शैक्षणिक संस्थान पर पहला दर्ज हमला 25 दिसंबर 2006 को हुआ था। यह हमला कोहाट जिले के दर्रा आदमखेल इलाके के नूर अली कलाई क्षेत्र में एक लड़कियों के स्कूल पर हुआ था। बम धमाके में स्कूल की इमारत के तीन कमरे पूरी तरह नष्ट हो गए थे। हमले से पहले कट्टरपंथियों ने कई मिडिल और हाई स्कूलों को धमकी भरे पत्र भेजे थे।

होर्मुज में बढ़ी जहाजों की आवाजाही, ईरान के तीन तेल टैंकरों ने अमेरिकी नाकेबंदी को किया पार

एजेंसी

तेहरान । होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ने लगी है। मैरीटाइम एनालिसिस फर्म विंडवर्ड ने बताया कि 14 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे, जो इस महीने का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है। जो इस महीने का अब तक का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा है। इस बढ़ोतरी को शिपिंग कंपनियों के बीच धीरे-धीरे लौटते भरोसे के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत सूचीबद्ध एक जहाज 'सोफिया 1' ने भी होर्मुज स्ट्रेट को पार किया। इसे पहले अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा ईरान के तेल परिवहन नेटवर्क से जुड़े जहाजों में शामिल किया गया था और इस पर द्वितीयक प्रतिबंध भी लगाए गए थे। समुद्री

गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था टैंकरट्रैकर्स के मुताबिक, पीस डील ऐलान के बाद से ईरान का तीसरा तेल टैंकर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को पार कर गया। टैंकरट्रैकर्स ने बताया कि नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी (एनआईटीसी) का टैंकर सोनिया-1 करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ था।

इससे पहले इसी सप्ताह एनआईटीसी के दो टैंकर डायोना और हीरो-2 भी अमेरिकी नाकाबंदी पार कर निकले थे। इन दोनों जहाजों में कुल 38 लाख बैरल ईरानी कच्चा तेल लदा था।

हालांकि, मौजूदा ट्रैफिक अभी भी युद्ध से पहले के स्तर से काफी कम है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, संघर्ष शुरू होने से पहले इस होर्मुज से औसतन करीब 130 जहाज प्रतिदिन गुजरते थे।

विंडवर्ड ने कहा कि कई शिपिंग कंपनियां अभी भी पूरा भरोसा जुटा नहीं पाई हैं, वो इंतजार कर रही हैं। जहाज मालिकों का कहना है कि वे तब तक होर्मुज से जहाज नहीं भेजेंगे, जब तक जहाजों पर हमले का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता।

रविवार को ही अपने 80वें जन्मदिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पीस डील का ऐलान करते हुए 'समुद्री जहाजों को अपने इंजन शुरू करने और तेल की आपूर्ति निर्बाध रूप से बहने देने' का संदेश दिया था। एमओयू पर ईरान ने भी बयान दिया, फिर दोनों के बीच ई-साइन भी हुए। दोनों पक्ष मध्यस्थों के बीच जिनेवा में 19 जून को दस्तखत करेंगे।

चीन ने संयुक्त राष्ट्र में 'ग्लोबल साउथ को पर्याप्त प्रतिनिधित्व' देने की वकालत की

एजेंसी

बीजिंग । चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक विवादों के कारण संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और प्रभावशीलता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, बुधवार को बीजिंग में 'वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत और समान बनाने' से जुड़े एक श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) को जारी करते हुए एक प्रेस वार्ता में वांग यी ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चाहे कोई देश बड़ा हो या छोटा, शक्तिशाली हो या कमजोर, विकसित हो या विकासशील सभी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समान सदस्य हैं। वांग ने वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के देशों की आवाज को अधिक महत्व देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया लगातार नई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे कई वैश्विक संकट एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'सभ्यता का जहाज अब खतरनाक जलक्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, जहां छिपी हुई चट्टानें और भीषण तूफान मौजूद हैं। ' वांग ने कहा कि मौजूदा विवाद गहरे और लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को उजागर करते हैं। उन्होंने 'ब्लैक स्वान' और 'ग्रे राइनो' जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अप्रत्याशित संकटों और स्पष्ट दिखने वाले लेकिन नजरअंदाज किए जाने वाले खतरों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

मध्य पूर्व की स्थिति पर वांग यी ने सभी पक्षों से तत्काल युद्धविराम की दिशा में काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए एक टिकाऊ सुरक्षा ढांचा विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी संबंधित पक्षों को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए, जो मध्य पूर्व में दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता की नींव रख सकें। वांग ने कहा कि व्हाइट पेपर का मकसद वैश्विक चुनौतियों के असरदार जवाबों पर अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाना है, और संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठा और केंद्रीय भूमिका को बनाए रखना इस पहल की सफलता के लिए जरूरी है।

मैं नहीं होता तो इजरायल तबाह हो चुका होता, लेबनान पर जिम्मेदारी से काम लें नेतन्याहू : ट्रंप

एजेंसी

एवियन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एवियन में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी संग संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान, इजरायल, लेबनान और ईरान से जुड़े मुद्दों पर कड़ा बयान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि अगर वो न होते तो इजरायल तबाह हो चुका होता। विभिन्न वैश्विक मुद्दों को लेकर थानी और ट्रंप के बीच बातचीत की। जी7 सम्मेलन से इतर ट्रंप ने अमीर से द्विपक्षीय बातचीत की। मुश्किल घड़ी में सयंम से काम करने के लिए प्रशंसा की और अमेरिका के लिए उन्हें अहम बताया। इस दौरान, ट्रंप ने इजराय, नेतन्याहू, ईरान समझौते और लेबनान को लेकर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा, 'इजरायल का अस्तित्व और उसकी सुरक्षा में अमेरिका की भूमिका निर्णायक रही है। उनके नेतृत्व के बिना इजरायल की स्थिति कमजोर हो सकती थी, क्योंकि अन्य कोई राष्ट्रपति वह कदम उठाने को तैयार नहीं था जो उन्होंने उठाए। ' बीबी (इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू) के साथ अपने संबंधों को 'बेहद अच्छा' बताया, लेकिन साथ ही कहा कि अब उन्हें 'लेबनान के संदर्भ में अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ' लेबनान की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, ' यह देश पहले शिक्षकों, डॉक्टरों और वकीलों के लिए जाना जाता था।

देशों के बीच रिश्ते दाता-प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि एकजुटता और परस्पर सम्मान पर आधारित होने चाहिए : प्रधानमंत्री

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित 'नई साझेदारियों का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के पुनर्निर्माण' विषयक आउटरीच सत्र में भाग लेते हुए वैश्विक सहयोग के लिए विश्वास और समानता पर आधारित साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज के परस्पर जुड़े हुए विश्व में देशों के बीच संबंध केवल दाता और प्राप्तकर्ता की सोच तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि एकजुटता, परस्पर सम्मान और समान भागीदारी पर आधारित होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा 'मानवता प्रथम' के सिद्धांत का पालन किया है। उन्होंने भारत की पहल पर स्थापित इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई), ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, मिशन लाइफ और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी प्रयास वैश्विक कल्याण और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की सोच 'वसुधैव कुटुंबकम्' अर्थात 'संपूर्ण विश्व एक परिवार है' की प्राचीन भारतीय भावना से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत समावेशी, टिकाऊ और सभी के लिए लाभकारी वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे विभिन्न देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की तथा समृद्धि, सतत विकास और मानव कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से भी मुलाकात हुई।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर जी7 नेताओं और विशेष आमंत्रित नेताओं की सामूहिक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें जी7 शिखर सम्मेलन में पारिवारिक तस्वीर खिंचवाने के लिए एकत्रित हुए। यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। ' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। नीस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंच पर भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया। भारत और फ्रांस ने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने तथा अधिक समृद्ध, सतत और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि एवियन पहुंचकर उन्हें विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि जी-7 देशों के नेताओं के साथ चर्चा हमेशा उपयोगी रहती है और भारत एक अधिक सतत तथा समृद्ध विश्व के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

page 1 and 8 June 18_page 1 Mar 25 final ds.qxd 6/18/2026 12:37 AM Page 2

स्थानीय समाचार

जम्मू नगर निगम ने कोट भलवाल डंपिंग साइट पर 5,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा

जम्मू,, 17 जून (हि.स.)। जम्मू नगर निगम ने कोट भलवाल डंपिंग साइट पर आज एक मेगा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का शुभारंभ आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने किया जिसमें अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन के सहयोग से लगभग 5,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति को सुधारना, हरित आवरण बढ़ाना और डंपिंग साइट के आसपास पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करना है। डॉ. यादव ने कहा कि पौधारोपण से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा, प्रदूषण कम होगा और क्षेत्र को अधिक स्वच्छ व हरित बनाया जा सकेगा।

कार्यक्रम में नगर निगम और वन विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया और इस परियोजना को सफल बनाने का संकल्प दोहराया।

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण-कठुआ में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन

कठुआ, 17 जून (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी जिला कठुआ द्वारा केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन रिवाज पैलेस लखनपुर में किया गया। कार्यक्रम में पार्टी

के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी रही।

इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा जम्मू-कश्मीर की पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में जिला प्रभारी प्रिया सेठी, जम्मू-कश्मीर भाजपा के महामंत्री बलदेव बिल्लोवरिया, सह-प्रभारी जिला कठुआ संजय बड्डू, भाजपा प्रवक्ता अंकुर शर्मा, विधायक कठुआ डॉ. भारत भूषण, जिला अध्यक्ष उपदेश अंडोत्रा, कार्यक्रम इंचार्ज रणजीत सिंह पठानिया एवं सह-इंचार्ज महाबीर सम्बयाल सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेताओं ने प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि आर्थिक क्षेत्र में भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत हाईवे, रेल, एयरपोर्ट और डिजिटल कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और जनधन योजना ने करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को नए अवसर प्रदान किए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भारत अधिक सशक्त हुआ है।

नेताओं ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भी बीते वर्षों में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास की रफ्तार तेज हुई है। पर्यटन, सड़क और रेल परियोजनाओं में तेजी आई है जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त किया गया है। निवेश और औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुले हैं जिससे युवाओं के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं।

1 किलो चरस के साथ दो नशा तस्कर गिरफ्तार

कठुआ, 17 जून (हि.स.)। नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने लखनपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 किलो चरस जैसे मादक पदार्थ के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना लखनपुर को क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने बसोहली मोड़ लखनपुर के पास विशेष चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका। तलाशी के दौरान वाहन सवार साहिल वर्मा निवासी वार्ड नंबर 2 कठुआ और उसके साथी मुकेश कुमार निवासी रोलका बनी के कब्जे से करीब 1 किलो चरस बरामद की गई। दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में थाना लखनपुर में एफआईआर नंबर 64/2026 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की नशा तस्करी या अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

हिन्दी के बढ़ते कदम- जम्मू मंडल राजभाषा समिति की बैठक संपन्न

जम्मू, 17 जून 2026। राजभाषा हिन्दी को कार्यालयीन कामकाज में और अधिक सशक्त बनाने के संकल्प के साथ उत्तर रेलवे, जम्मू मंडल की 'मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति' की तिमाही बैठक आज दिनांक 17 जून को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जम्मू के सभागार में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक, श्री विवेक कुमार ने की। बैठक में जम्मू मंडल के सभी शाखा अधिकारी एवं मुख्य कार्यालय अधीक्षक पूरे उत्साह के साथ उपस्थित रहे।

बैठक में मंडल रेल प्रबंधक, जम्मू श्री विवेक कुमार ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें राजभाषा के क्षेत्र में हमें अभी और आगे बढ़ना है। निरीक्षण के समय केवल तकनीकी काम ही न देखें, राजभाषा की प्रगति भी परखें और रिपोर्ट में इसका उल्लेख जरूर करें। फाइलों में कठिन शब्द नहीं, सहज-सरल हिन्दी का प्रयोग करें ताकि आम आदमी भी उसे आसानी से समझ सके। उन्होंने 'क' क्षेत्र में द्विभाषी और 'ख' व 'ग' क्षेत्र में त्रिभाषी सूत्र का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।

अपर मंडल रेल प्रबंधक सह अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री अक्षय कुमार मरन्टू ने सभी का स्वागत करते हुए अधिकारियों से आग्रह किया कि सर्वप्रथम पहले खुद हिन्दी में काम करें, फिर अपने साथियों को प्रेरित करें। हर कार्यालय प्रमुख अपने विभाग में हिन्दी कार्यों की मासिक समीक्षा करे, तभी लक्ष्य पूरे होंगे।

योग दिवस से पहले कठुआ में जागरूकता कैंप-हेल्दी एजिंग का दिया संदेश

कठुआ, 17 जून (हि.स.)। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन कठुआ और आयुष विभाग द्वारा बिरला पार्क कालीबाड़ी में योग जागरूकता एवं अभ्यास शिविर आयोजित किया गया।

योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग अपनाकर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डॉ. बोध पाल ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला जबकि योग प्रशिक्षक अंकुश मोडील ने विभिन्न आसन व प्राणायाम का अभ्यास करवाया। डॉ. नितन शर्मा ने तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका पर जानकारी दी। इस दौरान प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशामुक्त जीवन का संकल्प भी लिया।

शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी, मॉर्निंग वॉकर्स सहित करीब 70 लोगों ने भाग लिया और इस पहल की सराहना करते हुए योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों (ग्रेड-ए) को सीएम योगी ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र

लखनऊ, 17 जून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों (ग्रेड-ए) को बुधवार को लोकभवन में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं और पारदर्शी भर्ती को ससमय पूरा करने के लिए भर्ती बोर्ड को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के 'विकसित भारत' विजन को बढ़ाने के सारथी हैं। इसके लिए आत्म अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और आप इसे बनाए रखेंगे। ड्यूटी के प्रति सजगता और हर कार्य में गंभीरता होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे हंसी का पात्र बनना पड़े। सीएम ने विश्वास जताया कि सभी नवचयनित अभ्यर्थी यूपी पुलिस की आधुनिक तकनीक एवं सुरक्षा मानकों आदि की जानकारी के साथ टीम भावना, पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ अच्छा परफॉरमेंस देंगे।

सीएम ने कहा कि यूपी पुलिस ने जनसेवा को केंद्र में रखा तो देश में निखर गई। अब कोई यूपी पुलिस पर अंगुली नहीं उठाता। कालचक्र की परवाह किए बिना व्यक्ति अनिर्णय का शिकार होता है और अंततः बिखर जाता है। यूपी पुलिस की नई पहचान सिर्फ संख्या बल के आधार पर नहीं है। पीएम मोदी की अपेक्षा पर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूपी पुलिस ने 9 साल में जिस त्वरित गति से काम किया, वह मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है। नवचयनित कार्मिकों की स्मार्ट पुलिस व डिजिटल वॉरियर्स के रूप में बड़ी भूमिका होने जा रही है।

सीएम ने नवचयनित अभ्यर्थियों से 2017 के पहले के यूपी की चर्चा की और कहा कि उस समय आप सभी माता-पिता पर आश्रित रहे होंगे। उस उम्र में बहुत चिंता भी नहीं होती है, परंतु 10 वर्ष पहले पत्र-पत्रिकाओं, अखबारों की कतरनों का अवलोकन कीजिए, अभिभावकों व गुरुजनों से पूछिए कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, कानून व्यवस्था कैसी थी? प्रदेश के बारे में, पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी? औसतन हर दूसरे-तीसरे दिन दंगा होता था। उत्सव के पहले उपद्रव होता था, महीनों कर्फ्यू लगता था, लेकिन अब हर किसी को सुरक्षा मिल रही है। 9 वर्ष से यूपी में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा।

2017 के बाद बदली यूपी की तस्वीर, सीएम ने कहा- यूपी अब रेंग नहीं रहा, बल्कि दौड़ रहा

पुलिसकर्मियों को आत्म अनुशासन एवं जनसेवा पर विशेष जोर देने की सीख दी सीएम योगी ने

*2017 के पहले आईपीएस ही असुरक्षित थे तो नागरिक, महिला, व्यापारी कैसे सुरक्षित होते- सीएम योगी

*फाइलों में रह जाती थीं पुलिस की योजनाएं*मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की बात 1972 से चली आ रही थी, लेकिन कोई इसे लागू नहीं कर पा रहा था। मामला फाइलों में ही दबा रह जाता था। हमारी सरकार बनी तो 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया। यह पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। जिन लोगों को पुलिस रिफॉर्म या पुलिसिंग की जानकारी नहीं वे ही कमिश्नरेट सिस्टम पर अंगुली उठाते हैं। ये वही लोग हैं, जिनको आम नागरिकों की सुविधा व सुरक्षा की चिंता नहीं।

सीएम ने कहा कि 2017 के पहले पुलिस अधिकारी ही असुरक्षित थे। मुरादाबाद में डीआईजी स्तर के अधिकारी को उपद्रवियों ने घेरकर मारा था और उन्हें जीवित न मानकर छोड़ गए। सोचिए, जब राज्य में आईपीएस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं थे तो सामान्य नागरिक, महिला, बेटी-बहन, व्यापारी की सुरक्षा सिर्फ कल्पना थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौर में यूपी के लोगों ने सुधार की कल्पना करना ही छोड़ दिया था। डबल इंजन सरकार आने के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो अपराधियों को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव भी आए, लेकिन सरकार की अभियोजन शाखा के प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों पहले ही उन अपराधियों को इतनी गंभीर सजा मिली कि अब उनकी कई पीढ़ियां भी अपराध करना भूल जाएंगी। सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश के भर्ती आयोगों-बोर्डों में पारदर्शिता सुनिश्चित की। पिछले दिनों 35 हजार पुलिस आरक्षियों की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 28 लाख युवा शामिल हुए।

कठुआ के गायक सनी सलीम का धमाका- 'अल्लाह वे' गीत का भव्य विमोचन

कठुआ, 17 जून (हि.स.)। कठुआ शहर के उभरते गायक सनी सलीम के नए गीत अल्लाह वे का बुधवार को श्री विश्वकर्मा मंदिर कठुआ में भव्य तरीके से विमोचन किया गया। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों और कलाकारों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कठुआ विधायक डॉ. भारत भूषण उपस्थित रहे जबकि डीडीसी वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू और सभा के अध्यक्ष करतार वर्मा ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से गीत का विमोचन किया और गायक सनी सलीम को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी। इस मौके पर स्थानीय कलाकारों की भी शानदार मौजूदगी रही जिनमें दिलशेर हंस, बंटी अलमस्त, अकुश कुमार, अभिषेक भोगल, राहुल सूर्यवंशी, सुनील, शाम आलम, लक्की अमृतसरिया, विशाल, मानक शाह कोटी, आकाश, राहुल, मानीक सहित कई अन्य कलाकार शामिल रहे। सभी ने सनी सलीम के गीत की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं बल्कि युवाओं को अपनी कला के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। गायक सनी सलीम ने भी सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे आगे भी दर्शकों के लिए बेहतर संगीत प्रस्तुत करते रहेंगे

नशा मुक्त अभियान की समीक्षा, जागरूकता व सख्त कार्रवाई के निर्देश

कठुआ, 17 जून (हि.स.)। डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने बुधवार को नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर और नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत चल रही गतिविधियों की समीक्षा बैठक की।

बैठक में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी मजबूत करने, हेल्पलाइन तंत्र के प्रभावी संचालन तथा नशे के शिकार लोगों की पहचान व पुनर्वास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। डीसी ने संबंधित विभागों को जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के लाभ रद्द करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी चर्चा हुई। डीसी ने सभी हितधारकों से मिलकर कठुआ को नशामुक्त बनाने का आह्वान किया। बैठक में एसएसपी मोहित शर्मा सहित अन्य जिला अधिकारी मौजूद रहे।

सिविल डिफेंस का जागरूकता शिविर आयोजित, लोगों को दिए आपदा प्रबंधन और जीवनरक्षक तकनीकों के प्रशिक्षण

जम्मू, 17 जून (हि.स.)। सिविल डिफेंस जम्मू द्वारा छन्नी हिम्मत स्थित ग्रीन बेल्ट पार्क में एक दिवसीय सिविल डिफेंस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डीएसपी तजिंदर कौर जेकेपीएस प्रभारी उप नियंत्रक सिविल डिफेंस जम्मू के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर सिविल डिफेंस जम्मू के मुख्य वार्डन परमजीत कुमार तथा उप मुख्य वार्डन आर. विजय मगोत्रा ने भी कार्यक्रम के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जागरूकता शिविर में आसपास के क्षेत्रों के लगभग 40 स्थानीय निवासियों और मॉर्निंग वॉकर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड), अग्निशमन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) तथा अन्य जीवनरक्षक तकनीकों के बारे में व्यावहारिक और सैद्धांतिक जानकारी प्रदान की गई। सिविल डिफेंस टीम द्वारा विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए लाइव प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान हृदयाघात, गले में वस्तु फंसने, हड्डी टूटने तथा अन्य चिकित्सीय आपात स्थितियों में अपनाई जाने वाली जीवनरक्षक तकनीकों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया। प्रतिभागियों को आपदा या दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने और समय पर सहायता पहुंचाने के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉ. कस्तूरी लाल, इंडस्ट्रीज बाड़ी ब्राह्मणा के अध्यक्ष ललित गुप्ता, डी.एन. डोगरा, सरदार उज्जगर सिंह, इंजीनियर कुलदीप मंकोटिया, इंजीनियर गंडोत्रा, वरिंदर नंदा, वी.के. मगोत्रा, श्री एवं श्रीमती सुनील शर्मा सहित चन्नी हिम्मत क्षेत्र के अनेक मॉर्निंग वॉकर्स उपस्थित रहे।

ग्रीन बेल्ट पार्क मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य इंजीनियर परवीन बाली ने एसोसिएशन की ओर से सिविल डिफेंस जम्मू द्वारा आयोजित इस जनजागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आम लोगों को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वार्डन परमजीत कुमार और उप मुख्य वार्डन आर. विजय मगोत्रा ने प्राकृतिक आपदाओं, आगजनी, औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा अन्य संकटपूर्ण परिस्थितियों में सिविल डिफेंस वार्डनों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सिविल डिफेंस वार्डन आपदा की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करते हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं।

जम्मू-कश्मीर में राइज़ इन जम्मू-कश्मीर 2026 का शुभारंभ, SKICC श्रीनगर में राज्यसभा सांसद श्री गुलाम अली खटाना ने किया उद्घाटन

श्रीनगर, 17 जून। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं जागरूकता पहल राइज़ इन जम्मू-कश्मीर 2026 - विकसित भारत @ 2047 की ओर बढ़ता कदम का आज श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद माननीय श्री गुलाम अली खटाना ने किया, जिनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की परिकल्पना और आयोजन किया गया है।

तीन दिवसीय यह कार्यक्रम टर्मेह इवेंट्स द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान, विकास संगठन और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि एक साझा मंच पर भारत की विकास यात्रा, तकनीकी नवाचारों, प्रमुख योजनाओं और जनकल्याणकारी पहलों को प्रदर्शित कर रहे हैं।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गुलाम अली खटाना ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे परिवर्तनकारी कार्यों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर विकास और प्रगति के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है तथा ऐसे मंच नागरिकों को उन संस्थानों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं।

श्री खताना ने विकसित भारत @ 2047 के विजन पर प्रकाश डालते हुए सभी हितधारकों—सरकारी एजेंसियों, उद्योग जगत, शोधकर्ताओं और युवा नवप्रवर्तकों से विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी बुनियादी ढांचे, विज्ञान एवं तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं और सतत विकास के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदर्शनी में एनएचपीसी, बीआईएस, आईसीएमआर, इसरो, सीएसआईआर, आईसीएआर, एपीडा, नॉर्दर्न रेलवे, आईआरसीटीसी, सीपीसीबी, सर्वे ऑफ इंडिया, पावरग्रिड, हर्ल, एनएफएल, एनबीसीसी, आरईसी, एनटीपीसी, ट्राइफेड, नेशनल जूट बोर्ड, नेफेड और परमाणु ऊर्जा विभाग सहित कई प्रमुख संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम भाग ले रहे हैं।